A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 31 अगस्त, 2024

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 305, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

हरियाणा : जेजेपी के साथ चंद्रशेखर की एंट्री कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी

सौरव रॉय बर्मन

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने मंगलवार को चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता किया। यह कदम चुनावी राज्य हरियाणा में दलित वोटों को एकजुट करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल कर सकता है। अपनी ओर से, कांग्रेस ने गठबंधन को किसी काम का न बताते हुए कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जेजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था और आज़ाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में कोई मज़बूत संगठनात्मक ढांचा मौजूद नहीं है।

2011 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा की आबादी में अनुसूचित जातियों (SC) की हिस्सेदारी 20.2 प्रतिशत है, और 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। जो कि दिखाता है कि इस समुदाय का चुनाव के मद्देनज़र कितना महत्व है। परिणामस्वरूप, राज्य के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी- चाहे वह इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) हो या उसकी शाखा JJP, या कांग्रेस- सबने अतीत में बहुजन समाज पार्टी (BSP) को लुभाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें दलित समुदाय का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए दलित पार्टी का सहयोग लेना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। मुख्य रूप से यूपी की नगीना सीट से आज़ाद की लोकसभा जीत के कारण स्क्का उदय, अब इसे BSP जैसी ही स्थिति में ला खड़ा करता है।

हालांकि, हरियाणा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा रहे एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के पास जेजेपी-एएसपी गठबंधन को लेकर बहुत चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। अन्य कारणों के अलावा, उन्होंने बीएसपी की पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने के बावजूद राज्य में कोई खास पैठ बनाने में असमर्थता का हवाला दिया। इसने विधानसभा चुनावों में कभी भी एक से ज़्यादा सीटें नहीं जीती हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'हमें पूरा यकीन है कि इससे हमारा कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ होगा। हरियाणा में दलित, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह उत्तर प्रदेश से अलग है, जहां एएसपी ने कुछ सफलता का स्वाद चखा है।'

सीट बंटवारे के समझौते के तहत, जेजेपी राज्य की 90 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एएसपी शेष 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी इस बार हरियाणा में आईएनएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 2019 में, दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से पहले थोड़े समय के लिए गठबंधन किया था, लेकिन मतदान के दिन से पहले ही अलग हो गए थे। महीनों बाद, बीएसपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों से पहले उसी तरह से संबंध तोड़ लिए।

2019 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से सात कांग्रेस, पांच भाजपा, चार जेजेपी और एक निर्दलीय के खाते में गई थी। 2024 के आम चुनावों में, जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राज्य में पांच-पांच सीटें जीतीं, पर कांग्रेस ने दोनों आरक्षित लोकसभा सीटें बड़े अंतर से जीतीं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा ने कहा कि जेजेपी-एएसपी गठबंधन का 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में, जेजेपी का वोट शेयर 0.87 प्रतिशत था। एएसपी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है।'

कांग्रेस को यह भी लगता है कि जेजेपी के भाजपा के साथ पिछले गठबंधन और भाजपा के साथ भविष्य में संबंध बनाने पर उसके अनिर्णायक रुख से दलित समुदाय नाराज हो जाएगा। इस तरह के गठबंधन की संभावना को चौटाला ने खुला छोड़ दिया अगर 2019 की तरह चुनावों में वह किंगमेकर के तौर पर उभरते हैं तो, चौटाला ने भाजपा के साथ अपने समीकरण पर सवालों का जवाब देते हुए कहा, '2019 में कांग्रेस के साथ जाने से स्थिर सरकार नहीं बनती। भविष्य के बारे में कौन बता सकता है।'

2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, 10 विधायकों के साथ पहली बार चुनाव लड़ रही जेजेपी किंगमेकर के रूप में उभरी थी, जिसने जाटों का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया था, जो राजनीतिक दलों के अनुमान के अनुसार, राज्य की आबादी का 26 प्रतिशत है। चौटाला ने भाजपा का समर्थन किया और उपमुख्यमंत्री बने। लेकिन इस साल मार्च में, जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे, भाजपा ने जेजेपी के साथ अपने संबंध तोड़ लिए, जिससे वह मुश्किल में पड़ गई।

'पिछले कुछ दिनों में, इसके सात विधायकों ने जेजेपी छोड़ दी है। एक कांग्रेस में शामिल हो गया है, जबकि दो के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। चौटाला ने पार्टी छोड़ने की घटनाओं को कमतर आंकते हुए कहा कि संबंधित दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा को भी इसी तरह के विधायकों का सामना करना पड़ेगा। चौटाला ने चुनाव के बाद भाजपा के साथ हाथ मिलाने का विकल्प खुला रखा, लेकिन हरियाणा और पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन से पार्टी के निपटने के तरीके से खुद को दूर रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि उनका (चौटाला का) परिवार हमेशा किसानों के साथ रहा है।'

हालांकि, दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) के अध्यक्ष अशोक भारती ने कहा कि दलितों को पता है कि इन राजनीतिक मोर्चों को 'भाजपा द्वारा खुले तौर पर या गुप्त रूप से समर्थन और वित्त पोषण किया गया है।।' भारती ने कहा, 'हम हरियाणा में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और साफतौर पर देख सकते हैं कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। दलित मतदाता हारने वाले पक्ष का साथ देने के मूड में नहीं हैं। उनके दिमाग में यह बात भी चल रही है कि जेजेपी फिर से भाजपा के साथ जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौटाला ने अपने परदादा देवीलाल और बीएसपी संस्थापक कांशीराम के बीच संबंधों का हवाला देते हुए आजाद के साथ अपने गठबंधन को विरासत की निरंतरता के रूप में पेश किया।

चौटाला ने कहा, 'जब कांशीराम ने दिल्ली के बोट क्लब में बी.आर. अंबेडकर के लिए भारत रत्न की मांग को लेकर धरना दिया था, तो चौधरी देवीलाल (आईएनएलडी के संस्थापक) उनका समर्थन करने वाले पहले नेता थे। जब वे (देवीलाल) उप प्रधानमंत्री बने, तो अंबेडकर को न केवल भारत रत्न दिया गया, बल्कि संसद में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे और आजाद लंबे समय तक साथ रहे।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मत भूलिए, हम दोनों 36 साल के हैं।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

मेरी सारी और सतत अभिव्यक्तियां मेरे अतीत को
मिटाने की चल रही समानांतर प्रक्रिया है–
एक रेखा जितनी बढ़ती है–
पीछे एक लकीर ढलती चली जाती है–
मैं एक संदर्भ रहित प्रसंग का टुकड़ा हूं–
गूंजती ध्वनि का विलीन होता
सबसे आखिरी कतरा
ओझल होता
धुंधलका..
एक स्मृति जो निरंतर बहती है
विस्मृति की डोर से बंधी..!
एक विसर्जन
जो स्थापना के साथ घट चुका..!

– सारंग उपाध्याय

मैं सिर झुकाकर महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगता हूं

सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। मोदी ने कहा- छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं हैं; हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विरोध भी कर रही है। पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया। इससे पहले मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा-एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हूं। एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम 28 से 30 अगस्त तक आयोजित हुआ। इसमें 800 से ज्यादा स्पीकर और 80,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच भी कार्यक्रम में पहुंचीं।10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500त्न वृद्धि हुई है। सस्ते फोन-डेटा और जीरो बैलेंस बैंक खातों ने कमाल कर दिया है।

- **इससे पहले शिंदे-फडणवीस व अजित पवार भी मांग चुके माफी**

मध्यप्रदेश उत्सव से एमपी को जानने समझने का मिलेगा अवसर : सीएम

मुख्यमंत्री की अनूठी पहल,दिल्ली में पहली बार हुआ मध्यप्रदेश उत्सव का आयोजन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जनजातीय विरासत, पर्यटन, कला, रहन-सहन एवं विविध व्यंजन इत्यादि की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के दिल (मध्यप्रदेश) की समृद्ध, सांस्कृतिक धरोहरों से दिल्ली एवं अन्य प्रदेश के लोगों को परिचित कराने के लिये देश की राजधानी में 4 दिवसीय 'मध्यप्रदेश उत्सव' का अनूठा आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में 'मध्यप्रदेश उत्सव' का रंगारंग शुभारंभ कर यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर दिल्ली में पहली बार वृहद स्तर पर मध्यप्रदेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जो 30 अगस्त से 2 सितंबर, 2024 तक चलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उत्सव के आयोजन से दिल्लीवासियों एवं अन्य राज्यों से आये पर्यटकों को देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश की समृद्धशाली विविधताओं से परिपूर्ण संस्कृति सहित अन्य पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। आगंतुक न सिर्फ प्रदेश की समृद्ध विरासत को जानेंगे, समझेंगे बल्कि विविधताओं से भरे मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों में बनाये जाने वाले विशिष्ट व्यंजनों सहित सुपर फूड में 'श्रीअन्न' से निर्मित व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे।

झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल

- बोले-कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी, शिवराज ने कहा- टाइगर अभी जिंदा है

रांची (एजेंसी)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति-पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं, चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया।

गांवों में बढ़ेगा पर्यटन, अभी हैं 116 होम-स्टे, भविष्य में और बढ़ेंगे

- **गांव की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती**

भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ने से अब गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। प्रदेश में अभी तक 116 होम-स्टे हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जायेगी। ग्रामीण संस्कृति और परिवेश को समझने विदेशों और शहरों से पर्यटक आकर रुकने लगे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे गांवों की पहचान की जा रही है जिनमें पर्यटन की भरपूर संभावना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने सभी पंचायतों से आग्रह किया है कि वे अपने यहां पर्यटन की संभावना वाले गांवों की पहचान कर पर्यटन गांव बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छिंदवाड़ा के तमिया विकासखंड के झिरपा से 6 किलोमीटर अंदर 300 घरों का सावरवानी गांव 2019 से पर्यटन गांव बन चुका है। अब तक यहां 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने आकर गांव की संस्कृति, खान- पान की संस्कृति समझी। खेती-किसानी, पशुपालन की गतिविधियों को स्वयं शामिल भी हुए। इन पर्यटकों में दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूरोप, रूस, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के पर्यटक मुख्य रूप से शामिल है। सावरवानी में वे सब सुविधाएं हैं जो आदर्श गांव के लिए अनिवार्य हैं। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- **पर्यटन गांव बनाने प्रस्ताव भेजें पंचायतें : प्रहलाद पटेल**

गांवों की शांति और प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यहाँ शांत वातावरण में रुक कर आसपास के छोटे-छोटे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की सैर कर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं जैसे अनहोनी गर्म कुंड, अनहोनी मेला, सप्तधारा, चांवलपानी के पास स्थित खारा पानी दैविक कुंड, घोघरा वाटरफाल, तामिया, पातालकोट, मौनीबाबा की पहाड़ी के साथ झिंगरिया वाटरफाल। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन का बरगोदी गांव यहां से सटा हुआ है। पर्यटकों के लिए ब्रेक फास्ट, लंच और डिनर का पूरा पैकेज है। इसके अलावा बैलगाड़ी की सैर, गायों का दूध दुहना, उन्हें चारा खिलाना, खेती किसानी के छोटे-छोटे काम करना और पास की मोनाखेड़ी पहाड़ी में ट्रैकिंग की सुविधा, भजन मंडली और जनजातीय करमा नृत्य मंडली भी उपलब्ध होने से सावरवानी में रुकना यादगार बन जाता है और स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है। इस होम स्टे - वेदिका हिल्स का प्रबंधन गांव की पर्यटन विकास समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश्वर यदुवंशी है। उपाध्यक्ष श्री राम प्रसाद सलाम और सचिव श्री दुर्गेश हैं। समिति के 15 अन्य सदस्यों में श्री रमेश परतेती, श्री नरेश नागवंशी, श्री मनोज भोरवंशी शामिल है। हर सदस्य के पास पर्यटन की अलग-अलग गतिविधियों की संचालन की जिम्मेदारी है। प्रत्येक गतिविधि का शुल्क निर्धारित है। जैसे्र जनजातीय शैला नृत्य के लिए 1000 रूपये और भजन मंडली की प्रस्तुति के लिए 500 रूपये, गाइड के लिए 500 रूपये , देशी खाना बनाने के लिए 300 रूपये शुल्क है।

नयनाभिराम भरतीपुर

रायसेन में दीवानगंज से 35 किलोमीटर दूर शाहपुर ग्राम पंचायत के भरतीपुर गांव के होम-स्टे की ख्याति अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। दो साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई। इस होम-स्टे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आसपास का जंगल लुभावना है। यहां से मात्र दो किलोमीटर दूर सोनाली बौद्ध स्तूप है। इस स्थान पर भी साल भर सतत् बहने वाला झरना है। इससे घने जंगल की पृष्ठभूमि में अनूठा दृश्य उपस्थित होता है। यहां पर्यटक अपने मनपसंद का देशी खाना खा सकते हैं विशेष रूप से दाल-बाटी। पर्यटक शांत वातावरण में गहन इतिहास बोध के साथ आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति कर सकते हैं।

समिति के उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद बताते हैं कि पास में ही तीन-चार किलोमीटर की दूरी में शाहवन और पुरातला गांव है। यहां के लोगों का भी अब रुझान बढ़ रहा है और अब ऐसे 6 होम-स्टे बन गए हैं। समिति के सचिव श्री दुर्गेश बताते हैं कि पर्यटकों के आने से गांव की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है। इस साल पर्यटकों ने 350 किलो प्राकृतिक रूप से उगाया गया गेंहू खरीदा। पर्यटक यहां से दूध, दही और सब्जी भी ले जाते हैं। ज्यादा फायदा घी बनाने वालों को हुआ है। पहले घी बनने के बाद बेचने के लिए रविवार के हाट बाजार का रास्ता देखा जाता था। अब पर्यटक उनके घर से ही खरीद लेते हैं। वर्तमान में देशी घी 800 प्रति किलो है और यह इस भाव में आसानी से बिक जाता है। अलावा यहां उगा हुआ चावल विशेष रूप से बासमती चावल भी हाथों-हाथ बिक जाता है। मक्का, ज्वार और बाजरे की रोटियां, पराठे और भजिए एवं अन्य व्यंजन काफी पसंद किए जाते हैं। टमाटर की चटनी और मक्के की रोटी विशेष रूप से पसंद की जाती है। स्थानीय सब्जियों की भी मांग रहती है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 36.3 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे
इंदौर ■ शनिवार, 31 अगस्त 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

भाकपा द्वारा सपनि फिर से चालू करने की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आन्दोलन के तहत विभिन्न जिलों में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मांग के पूरी होने तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी क्रमबद्ध आन्दोलन करने की घोषणा की है।

भोपाल में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर इकबाल मोहम्मद को सौंपा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ज्ञापन में यह उल्लेखित है कि 'मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम बन्द करने के दुष्परिणाम अब सामने हैं। निजी बसों में जनता प्रताड़ित हो रही है। निजी बसों में मनमानी किराया वृद्धि कभी भी कर दी जाती है। निजी क्षेत्र की खटारा बसों के कारण प्रति दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सब पर मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। सारे देश में संभवतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही ऐसे दो प्रदेश हैं जिनमें राज्य सरकार का सड़क परिवहन निगम नहीं है।अन्य प्रदेशों में सरकार द्वारा जनता को प्रदत्त सड़क परिवहन की बेहतर सुविधाओं से जनता लाभान्वित हो रही है लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इससे वंचित है। '

भोपाल में हुए भाकपा के प्रदर्शन को भाकपा के राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने संबोधित किया तथा इस मुद्दे को सरकार की सक्षमता से जोड़ते हुए सरकार की भर्त्सना की तथा जनहित में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग की।

प्रदर्शन में भाकपा के कार्यवाहक भोपाल जिला सचिव कॉमरेड मुन्ने खां ,अजय राऊत ,लाखन सिंह , महफूज अल्तमश,मानस भारद्वाज ,सुरेन्द्र अर्गल, जमुना प्रसाद,राजू खान , नईम, हसीम ,शानू भाई, मुवीन कुरेशी आदि शामिल थे।

भारत के आसमान में भी मिलेगी इंटरनेट की सुविधा

इसरो ने शुरू की बड़ी तैयारी,वी-सैट कंपनी भी करेगी मदद

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय आसमान में उड़ते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमाएं जल्द ही खत्म हो सकती हैं। दरअसल अभी तक भारत में हवाई जहाजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद लिमिटेड है। कुछ ही साल पहले ये सीमित सुविधा दी गई थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है। कैलिफोर्निया स्थित ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी, वाय सैट, भारतीय आसमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की तैयारी में है। भारत के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, खासकर तब जब देश इस साल के अंत में अपने सबसे हाई-टेक सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो यह सैटेलाइट भारतीय आसमान में इंटरनेट सेवाओं को और भी सुलभ और प्रभावी बना सकता है। इस दमदार सैटेलाइट (हाई थ्रूपुट सैटेलाइट) का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट एक ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जो पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत हाई स्पीड पर डेटा भेज सकता है। जीसैट-20 का लॉन्च भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो उड़ान के दौरान इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं। इससे न केवल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि क्षमता का पांचवां हिस्सा इन-फ्लाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए आरक्षित किया जा रहा है।

रिमोट जगहों को जोड़ना वैश्विक सैटेलाइट कंपनी वायसैट इंक का एक बड़ा उद्देश्य है। इसकी पहले से ही बड़ी उपस्थिति है क्योंकि यह भारतीय सशस्त्र बलों को भी विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हालांकि, भारत में एक बड़ी कमी इन-फ्लाइट इंटरनेट की है।

संसदीय विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा मप्र के विद्यालयों तथा भोपाल के विवि, महाविद्यालयों के युवा संसद प्रभारियों के लिए ऑन लाइन अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें करीब 100 युवा संसद प्रभारियों ने ऑन लाइन भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, विशिष्ट अतिथि, डॉ. एन.के. थापक, कुलगुरू, एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय एवं डॉ. धर्मेन्द्र पारे, निदेशक, जनजातीय संग्रहालय उपस्थित रहे। प्रारंभ में डॉ. प्रतिमा यादव, संचालक ने विद्यापीठ की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवा संसद प्रतियोगिता में युवा संसद प्रभारियों की भूमिका बहुत ही अहम एवं महत्वपूर्ण रहती है। उनके द्वारा किए गए प्रयास ही विद्यार्थियों के मंचन में परीलक्षित होते हैं। युवा संसद मंचन के आयोजन हेतु संसदीय विद्यापीठ द्वारा पृष्ठाधार सामग्री, उदहारण स्वरूप मंचन की डी.व्ही.डी. तथा प्रति शिक्षण संस्थान को रुपये 10 हजार रू. आवंटित किए जाते हैं।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में ए.बी. आचार्य, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने युवा संसद से संबंधित क्रमवार सैद्धांतिक जानकारी प्रदान की तथा प्रभारियों के प्रश्नों का जवाब दिया। द्वितीय सत्र में पुनीत श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय द्वारा युवा संसद से संबंधित व्यवहारिक जानकारी दी। अंत में सागर पब्लिक स्कूल, कटारा एक्सटेंशन, भोपाल द्वारा किए गए युवा संसद मंचन की ऑन-लाइन क्लिपिंग दिखाई गई।

असम विधानसभा में खत्म हुआ अब जुमा ब्रेक

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम की विधानसभा में जुमे यानी शुक्रवार के दिन मिलने वाले दो घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने

- **हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा-यह औपनिवेशक दौर की परंपरा थी**

एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि यह औपनिवेशक दौर की परंपरा थी, जिससे असम विधानसभा ने मुक्ति पा ली है। उन्होंने ट्वीट किया ,दो घंटे का जुमा ब्रेक असम विधानसभा ने खत्म कर दिया है। इससे काम और उत्पादकता पर असर पड़ता था। इसके साथ ही हमने औपनिवेशिक काल की एक और परंपरा को खत्म कर दिया। इस प्रथा को मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू किया था।

इसके आगे उन्होंने लिखा, मैं असेंबली स्पीकर और अपने विधायकों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनका आभारी हूं। इस तरह अब असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए मिलने वाला दो घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा। असम सीएम ने कहा कि इस फैसले के जरिए हम विधानसभा की उत्पादकता को प्राथमिकता दी है। भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन ने कहा कि ब्रिटिश काल से असम असेंबली में हर शुक्रवार को नमाज के लिए 12 से 2 बजे तक का ब्रेक दिया जाता था। अब यह नियम बदल गया है और ब्रेक नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम असेंबली के स्पीकर बिस्वजीत की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसका सभी विधायकों ने समर्थन किया।

आंध्र में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में मिला खुफिया कैमरा, भारी बवाल

- लड़कों के छात्रावास में भेजी जाती थी क्लिप,कई वीडियो मिलने से हड़कंप

हैदराबाद (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़कियों के हॉस्टल के

वॉशरूम में हिडेन कैमरा बरामद हुआ है। खुफिया कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। छात्राओं का आरोप है कि यहां गुडलवालेरु कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के गर्ल्स हॉस्टल में हिडन कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि छिपे हुए कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो कथित तौर पर लड़कों के छात्रावास में छात्रों के बीच प्रसारित किए गए। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र को भी हिरासत में लिया है।

आपका जवाब नहीं मिला...

सीएम ममता बनर्जी ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र

गिनाए अपने काम,की कड़े कानून बनाने की मांग

कोलकाता (एजेंसी)। ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हत्या और रेप की बर्बर घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले के पत्र का जवाब उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं मिला है इसलिए उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है। बनर्जी ने लिखा, मैंने 22 अगस्त को आपको पत्र लिखा था और रेप की जघन्य घटनाओं के खिलाफ केंद्र द्वारा कड़े कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की थी। हालांकि मुझे अब तक पत्र का जवाब नहीं मिला। ममता ने कहा, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मुझे जवाब

जरूर दिया गया था। हालांकि यह विषय की गंभीरता के मुताबिक नहीं था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के सामान्य जवाब की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा हमारे राज्य में इस मामले में कुछ बड़े काम किए गए हैं, जवाब में उनको भी नजरअंदाज किया गया था। ममता बनर्जी ने पत्र में कहा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर बात करें तो 10 विशेष पॉक्सो कोर्ट की मंजूरी राज्य सराकर ने दी है। इसके अलावा 88 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और 62 पॉक्सो कोर्ट काम कर रहे हैं जो कि राज्य के फंड पर ही चलते हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जानी थी। हालांकि माननीय हाई कोर्ट का कहना है कि इन अदालतों में भी स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे में आपके दखल की जरूरत है ताकि केंद्र सरकार जरूरी ऐक्शन ले सके। चइसके अलावा राज्य में हेल्पलाइन 112 और 1098 अच्छी तरह काम कर रही है।

अरिहंत के बाद अब नौसेना को मिला आईएनएस अरिघात

- 750 किमी तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों से है लैस, पाक-चीन को टेंशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को गुरुवार को

विशाखापतनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी के शामिल होने से नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तथा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।

अब कुमारी शैलजा को भी मिल सकता है टिकट

- हरियाणा कांग्रेस का यू-टर्न, सीएम फेस के लिए बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ (एजेंसी)। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी का कोई सांसद हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, बशर्ते उनके पास नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन हो। पार्टी महासचिव और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने इससे एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देख जा रहा है। इनमें से दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा सांसद हैं।

सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की बढ़ी रफ्तार

आंकड़ा पहुंचा 82 हजार के पार, अब तक सबसे ज्यादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दस साल में इमसें आठ गुना का इजाफा हुआ है। वहीं, सिर्फ दो बार बढ़ते केसेज पर लगाम लगाई गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की संख्या 83 हजार के करीब है जो अब तक की सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 2009 में बढ़ाकर 26 से 31 कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसेज में कोई कमी नहीं आ रही है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसेज 50 हजार से बढ़कर 66 हजार तक पहुंच गए थे। हालांकि 2014 में यह घटकर 63 हजार तक आ गए थे। उस वक्त सीजेआई पी सतसिवम और आरएम लोढ़ा थे। बाद में सीजेआई एचएल दत्तू के कार्यकाल के दौरान 2015 में सुप्रीम कोर्ट में

पेंडिंग केसेज की संख्या 59 हजार थी। अगले साल यानी 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की संख्या 63 हजार तक पहुंची। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर थे। बाद में जस्टिस जेएस खेखर के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की संख्या घटकर 56 हजार तक आ गई थी। जस्टिस खेखर ने ही अदालतों में पेपरलेस वर्किंग का प्रस्ताव दिया था। 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के सीजेआई रहते हुए पेंडिंग केसेज फिर से बढ़ने लगे थे और 57000 तक पहुंच गए थे। इसके बाद आए सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए मना लिया था। लेकिन जजों की संख्या बढ़ने के बाद केसेज भी बढ़े और पेंडेंसी बढ़कर 60 हजार केसेज की हो गई। जस्टिस एस बोबडे के कार्यकाल में कोरोना महामारी आई और मामलों की सुनवाई ठप पड़ गई।

आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार को राहत

- हाई कोर्ट ने रद्द की सीबीआई जांच,कैबिनेट का फैसला बरकरार

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही सीबीआई जांच को लेकर बड़ा मोड़ आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कैबिनेट द्वारा सीबीआई जांच को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। यह मामला तब सामने आया था जब 2019 में सरकार ने सीबीआई को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति दी थी। इसके बाद 2020 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।

विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार में रार

आपस में ही शुरू हो गई अपमान-स्वाभिमान की पॉलिटिक्स

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार में मंत्री तानाजी सांवत के ताजा बयान से राज्य की राजनीति में सियासी भूकंप आ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने सावंत के बयान को अजित पवार के अपमान से जोड़ दिया है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि क्या

- **शिंदे गुट के नेता तानाजी सांवत के बयान पर सियासी तूफान**

शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

पार्टी ने सीएम शिंदे को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है। तानाजी सावंत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वह शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक में जब मैं अजित पवार के बगल में

बैठता हूं तो उल्टी आती है। अब देखना है कि सीएम शिंदे सावंत पर क्या कार्रवाई करते हैं। एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है कि तानाजी सावंत ने यह बयान बीजेपी और शिंदे के इशारे पर दिया है। तापसे के अनुसार अजित पवार के बारे में सीएम शिंदे जो सोचते हैं वही बात तानाजी सावंत ने कही है। शरद गुट के प्रवक्ता तापसे ने कहा कि अजित पवार एक स्वाभिमानी नेता हैं। इसके साथ सवाल खड़ा किया है कि क्या वे सत्ता की लालच में अब भी सरकार में बने रहेंगे। तानाजी सावंत के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा या तो वह (तानाजी सांवत) रहेंगे या फिर एनसीपी। पाटिल ने यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें (एनसीपी) महायुति मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए।

लोकसभा चुनावों में महायुति के कमजोर प्रदर्शन के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर में अजित पवार पर निशाना साधा गया था लेकिन इस सांवत के बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी आक्रोशित हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या एनसीपी अजित पवार के अपमान को मुद्दा बनाकर महायुति से बाहर निकलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों महायुति के सब ठीक नहीं होने का दावा कर रहे हैं।

इंदौर में बड़ी बहन की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने की आत्महत्या

इंदौर(एजेंसी)। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में एक किशोरी अपनी बड़ी बहन की डांट से इतनी क्षुब्ध हुई कि उसने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आजाद नगर के मदीना नगर में रहने वाली नौवीं की छात्रा आविया फरीद शाह ने गुरुवार रात फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच में पता चला है कि अविया अपनी सहेली के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी। आविया अपनी सहेली के साथ स्कूल से छुट्टी लेकर सहेली के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। यह बात जब आविया की बड़ी बहन को पता चली तो उसने डांट लगाई। गुरुवार की देर शाम को आविया किचन में किसी काम का बहाना बनाकर गई और उसने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल भेजा और शुक्रवार को उसका पोस्टमार्ट्म किया गया। आविया के पिता ने बताया है कि दो दिन पहले उनकी बेटी स्कूल नहीं गई और अपनी सहेली के साथ उसके मित्र से मिलने जा पहुंची। यह बात तब पता चली जब आविया की बड़ी बहन टिफिन लेकर स्कूल पहुंची थी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि आविया स्कूल आई ही नहीं है। उसके बाद पता चला कि वह अपनी सहेली के साथ उसके दोस्त से मिलने गई थी। इस मामले को छुपाने के लिए आविया के सिर पर सहेली ने किसी मजबूत चीज से हमला किया और खुद को भी घायल कर लिया। उसके बाद दुर्घटना होने की बात कही। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों आविया की सहेली के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थीं।

एमएससी केमेस्ट्री, कार्बनिक रसायन और एमबीए एचए में पहली बार मिलेंगे चार नए पदक

इंदौर(एजेंसी)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2022-23 सत्र के मेरिट विद्यार्थियों को स्वर्ण व रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस बार समारोह में चार नए पदक दिए जाएंगे। ये सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। स्वर्ण व रजत पदक अलग-अलग संकाय में रखे गए हैं। इन्हें कार्यपरिषद की तरफ से मंजूरी मिली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन अब मेरिट विद्यार्थियों की सूची बनाकर पोर्टल पर अपलोड करेंगा। इस बार स्नातकोत्तर कार्बनिक रसायन में स्व. रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव की स्मृति में स्वर्ण पदक, एमबीए एचए में को स्व. सूरजकली द्विवेदी मेमोरियल एडवांस्ड होम्योपैथी स्वर्ण पदक, एमएससी केमेस्ट्री में स्व. सतीशकांत जैन स्मृति स्वर्ण पदक और स्व. दुर्गादेवी शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक रखे है, जो अलग-अलग संकाय के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। पदक के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। समारोह में 120 स्वर्ण पदक रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉ. शंकरदयाल शर्मा स्वर्ण पदक भी रखा है। ये पदक सरकारी-निजी कॉलेजों के विद्यार्थी को मिलता है। पदक के लिए कुछ मापदंड रखे है। उन पर विद्यार्थी को खरा उतरना पड़ता है। इसके लिए अकादमी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूरी है। वैसे एनएसएस और एनएससी की गतिविधियों से जुड़े छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता रहती है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन पदक के लिए कॉलेजों से अपने-अपने विद्यार्थियों के नाम मांगवाएंगे। इसके बाद समिति इन आवेदनों की स्क्रूटनी करेंगी। चुनिंदा आवेदन की जांच करने के बाद विद्यार्थी का नाम तय किया जाएगा। बाद में छात्र को समारोह में पदक दिया जाएगा।

नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट ने पकड़ा तूल

ओटी नर्सिंग स्टाफ ने काम किया बंद, नारेबाजी, जूनियर डॉक्टरों के माफीनामा पर काम किया शुरू

इंदौर(एजेंसी)। एमवाय हॉस्पिटल में गुरुवार को जूनियर डॉ. प्रवीण मिश्रा और डॉ. हेमंत द्वारा नर्सिंग ऑफिसर सुनील मेवाड़ के साथ हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। शुक्रवार को हॉस्पिटल के ओटी के नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर पहुंचे लेकिन ऑपरेशन थिएटर में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने घटना के विरोध में नारेबाजी की। उनकी मांग की कि डीन-सुपरिनटैंडैंट मामले में डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें अन्यथा वे उग्र आंदोलन करेंगे। हंगामे के बाद मारपीट करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने माफीनामा लिखकर दिया। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स काम पर लौट गए। गुरुवार को एक मरीज के ऑपरेशन के बाद सैंपल बायोप्सी के लिए नहीं भेजे जाने पर डॉक्टरों ने नर्सिंग ऑफिसर को पीटा था। शुक्रवार सुबह 8 बजे नर्सिंग ऑफिसर्स ड्यूटी पर पहुंचे लेकिन जिनकी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी है उन्होंने काम नहीं किया। कुछ देर बाद मप्र नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश कुमार जाट के साथ अन्य नर्सिंग ऑफिसर्स हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में सुपरिनटैंडैंट डॉ. अशोक यादव नहीं थे। इस पर उन्होंने उन्हें फोन कर हॉस्पिटल आने की मांग की है। कुछ देर बाद डॉ. यादव पहुंचे तो नर्सिंग ऑफिसर्स ने विरोध जताया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर वर्षा रहांगडाले ने भी घटना को लेकर जानकारी दी। डॉ. यादव ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते करने प्रयास किया। साथ ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो तीन दिन में रिपोर्ट सौंपेंगी।

अस्पताल संचालक के साथ की मारपीट, एक्सीडेंट करके भागने का आरोप लगाया

इंदौर(एजेंसी)। इंदौर के भंवरकुआ में कार से टक्कर लगने की बात पर एक अस्पताल संचालक के साथ कार सवारों ने मारपीट की। उन्होंने संचालक के माता-पिता को भी पीट दिया और कपड़ों की जेब से रुपए निकाल लिए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार सवार की तलाश शुरू कर दी है।भंवरकुआ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह लोधी की शिकायत पर कार में सवार युवकों पर केस दर्ज किया गया है। संदीप सिंह लोधी ने बताया कि वह सिटी अस्पताल के संचालक है। गुरुवार रात अपने परिवार के साथ राजीव गांधी चौराहे से तीन इमली की तरफ जा रहे थे।

राजबाड़ा क्षेत्र में स्वागत मंचों से व्यापारी त्रस्त, कोर्ट ने कहा, निगम सख्ती से प्रतिबंध लगाए

इंदौर(एजेंसी)। राजबाड़ा के आसपास आए दिन होने वाले राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों की वजह से यहां के व्यापारियों का व्यापार ठप हो जाता है। वहीं त्योहारों के सीजन में दुकानों के सामने रोड पर लगने वाली फुटपाथी दुकानों की वजह से भी कारोबार प्रभावित होता है। इस समस्या से निपटने के लिए व्यापारियों ने पहले तो निगमायुक्त को शिकायत की थी, लेकिन स्थायी हल नहीं निकला तो हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने व्यापारियों की अर्जी पर फैसला दिया है कि निगमायुक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 322 का सख्ती से पालन कराएं। व्यापारियों की ओर से सन्नी परियानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल, जन्माष्टमी के समय राजबाड़ा पर आयोजन होते थे। परियानी ने ही व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए आयोजन निरस्त कर दिया था। व्यापारियों का कहना है, जब भी कोई आयोजन होता है, सबसे पहला काम दुकानों के ठीक सामने मंच लगाने का किया जाता है। वहीं पुलिस द्वारा रोड बंद करवा दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि व्यापारी या तो अधिकांश समय दुकान पर खाली बैठे रहते हैं या फिर दुकान बंद करना पड़ती है। नेता या उनके समर्थक दुकानों के बाहर ओटले पर जाकर बैठ जाते हैं और

व्यापारियों से ही पानी, कुर्सी जैसी चीजें मांगते हैं। कई बार सामान गायब हो जाता है।

म्युनिसिपल एक्ट की यह ताकत

इस सेक्शन के तहत सड़कों पर किसी तरह स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मंच, ठेले, गुमटी रखकर भी सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों का भविष्य में उल्लंघ न हो।

35 से ज्यादा अवसरों पर 150 से अधिक मंच लगते हैं

राजबाड़ा क्षेत्र के आसपास (जवाहर मार्ग भी शामिल) विभिन्न समाजों के जुलूस, रंगपंचमी की गेर, झांकी से लेकर अन्य धार्मिक आयोजनों से जुड़े 35 से ज्यादा मौकों पर डेढ़ सौ से ज्यादा मंच लगते हैं।

कोई भी आयोजन होने से पहले संबंधित क्षेत्र के व्यापारियों से अनापत्ति ली जाए- हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा निगमायुक्त को प्रेजेंटेशन दिया गया था। इसमें उन्होंने समस्याएं बताई थीं। इसमें कहा है कि कोई भी आयोजन होने से पहले संबंधित क्षेत्र के व्यापारियों से अनापत्ति ली जाना चाहिए। इसके बिना आयोजन की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने व्यापारियों के प्रेजेंटेशन पर 15 दिन में सुनवाई कर निर्णय पारित करने के आदेश निगमायुक्त को दिए हैं।

राजबाड़ा के व्यापारी ही पीड़ित नहीं, और भी सड़कों पर व्यापारी, जनता परेशान हैं

मालवा मिल से भमोरी जाने वाले रोड के दोनों तरफ भी व्यापारी परेशान हैं। यहां सब्जी की दुकान रोड पर और उसके आगे ठेले लगे हुए हैं। अतिक्रमण की दो लेयर हो गई। दुकान ही नजर नहीं आती है। दुकान तक जाने का रास्ता भी ग्राहकों को नहीं मिलता है। यहां निगम द्वारा कभी कार्रवाई नहीं की जाती। आड़ा बाजार में भी दुकानों के बाद फेरीवाले खड़े रहते हैं। दो पहिया वाहनों के गुजरने लायक रास्ता भी नहीं बचता है।

लबालब बांध : मालवा-निमाड़ का कंठ तरबतर, खोलने पड़ रहे हैं डैम के गेट

इंदौर (एजेंसी)। नर्मदा में भरपूर पानी आने से इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध में भी पानी प्रचुर भर गया है। इसी तरह खरगोन, बड़वानी, उज्जैन के गंभीर बांध, शाजापुर के चिलर बांध, मंदसौर के गांधीसागर डैम सहित अन्य बांधों में भी प्रचुर जलराशि जमा हो गई है।इससे आने वाले पूरे वर्ष के लिए जल आपूर्ति की चिंता मिट गई है। वहीं, किसान भी खेती की सिंचाई को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। खंडवा जिले में इस वर्षाकाल में औसत वर्षा 808 मिमी की तुलना में अब तक करीब 620 मिमी वर्षा हुई है।

12 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी

ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी से इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध लबालब हो चुके हैं। इनका जलस्तर नियंत्रित करने के लिए गेट भी खोलना पड़े हैं। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर लगभग 262.05 मीटर है। जबकि पूर्ण जलभराव क्षमता 262.13 मीटर है।इसके 12 गेट छोड़ कर 3516 क्यूमेक्स पानी छोड़ रहे हैं। वहीं, ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर 195.40 मीटर रहने से इसके भी 12 गेट खोलकर 3321 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध की पूर्ण जलभराव क्षमता 196.10 मीटर है।

नर्मदा नदी का बढ़ गया है जलस्तर

इसके अलावा दोनों बांधों की आठों टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादन से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ। शहर की जलापूर्ति करने वाला नागचून तालाब अभी करीब 13 फीट खाली है। इसकी पूर्ण जलभराव क्षमता 1100 फीट है। वहीं, भगवंत सागर बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इस वर्ष मानसून का दौर आधे से अधिक बीत चुका है लेकिन जोरदार वर्षा के अभाव में स्थानीय नदी-नाले उफान पर आने जैसी स्थिति नहीं बनी है। शाजापुर जिले में अभी भी तेज वर्षा का इंतजार है। 23 फीट क्षमता वाले चीलर डेम का जल स्तर 17.6 फीट पहुंचा है। सभी प्रमुख नदियों में 32 से ज्यादा स्टॉपडैम हैं, जिनके गेट अभी बंद नहीं किए गए हैं। जिले की औसत वर्षा 987.7 मिमी है। झाबुआ जिले के सभी बांध लबालब हो गए हैं। माही नदी पर बना बांध लबालब हो गया है। इसके दो गेट खोले गए हैं।

ध्वनि प्रदूषण मामले में श्वेतांबर जैन मंदिर- कलेक्टर को नोटिस

हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई हुई, दो हफ्ते में मांगा जवाब

इंदौर(एजेंसी)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ ने तिलक नगर और सांईनाथ कॉलोनी में ध्वनि प्रदूषण के मामले में धार्मिक संस्थानों और राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। श्वेतांबर जैन मंदिर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर तय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां कभी भी आयोजन कर ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मामले में कोर्ट ने कलेक्टर और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सहित मंदिर की प्रबंध कार्यकारिणी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही अधिकारियों को नियमों का पालन करवाने के भी डायरेक्शन दिए हैं। याचिकाकर्ता शैलेष उध्वरिषे की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष मिश्रा ने बहस की गई। याचिका इन क्षेत्रों में कुछ धार्मिक संस्थानों द्वारा लगातार और अत्यधिक ध्वनि विस्तारकों के उपयोग पर केंद्रित है। जिससे स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को गंभीर परेशानी हो रही है। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने 2015 में राजेंद्र कुमार वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में पारित एक आदेश का संदर्भ दिया, जिसमें ध्वनि स्तर प्रतिबंधों के अनिवार्य अनुपालन को रेखांकित किया गया था, जैसा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत है। न्यायमूर्ति वर्मा ने राज्य अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ध्वनि स्तर तय सीमा से अधिक न हो।

धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं, कोर्ट ने इन्हें अवमानना नोटिस जारी की

इंदौर(एजेंसी)। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने नकार दिया है। साथ ही संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा को अवमानना नोटिस जारी किया है।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति संबंधित आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा पर नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बसंल ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। खंडवा निवासी लव जोशी तथा शेख जावेद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाए जाने के आदेश जारी किए थे। खंडवा में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में जनवरी 2024 में सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कहा गया था,

कोलाहल एक्ट की धारा-7 के तहत धार्मिक स्थलों में निर्धारित ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करें।याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक्ट में दिए गए प्रावधान के तहत जिला कलेक्टर खंडवा तथा संभागायुक्त इंदौर के समक्ष आवेदन पेश किया। आवेदन पर उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश जारी किया था कि 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि में आवेदन का निराकरण किया जाए।निर्धारित समय अवधि के बाद भी दोनों अधिकारियों ने आवेदन का निराकरण नहीं किया, जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है।

सिंहस्थ से पहले कान्ह और सरस्वती नदी होगी कब्जे से मुक्त, डेढ़ हजार निर्माण टूटेंगे

इंदौर(एजेंसी)। कलेक्टर आशीष सिंह ने अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों की बैठक भी ली है। नदी के कब्जे हटने से इंदौर में जलजमाव की समस्या भी दूर हो जाएगी। सिंह ने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कब्जे हटाने के लिए कहा है। सर्वे के बाद डेढ़ हजार अतिक्रमण चिन्हित किए है। चार साल बाद उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेल के लिए शिप्रा नदी शुद्धिकरण की शुरुआत इंदौर से होगी। कान्ह और सरस्वती नदी शिप्रा में मिलती है और सबसे ज्यादा यह दोनो नदियां ही शिप्रा को प्रदूषित करती है। इंदौर नगर निगम दोनो नदियों को प्रदूषण से मुक्त करेगा। पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके लिए उसके आसपास से कब्जे भी हटाए जाएंगे।कलेक्टर आशीष सिंह ने अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों की बैठक भी ली है। नदी के कब्जे हटने से इंदौर में जलजमाव की समस्या भी दूर हो जाएगी। सिंह ने कहा कि

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कब्जे हटाने के लिए कहा है। सर्वे के बाद डेढ़ हजार अतिक्रमण चिन्हित किए है। प्रभावितों को आवास भी दिए जाएंगे। नदी के आसपास 30 मीटर तक कब्जे हटाए जाएंगे। इंदौर के कबीटखेड़ी क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से 300 एमएलडी क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, लेकिन शहर का फैलाव निरंजनपुर, लसुड़िया, मांगलिया तक हो चुका है और वहां भी सीवरेज का पानी नदी में मिल रहा है।

इन क्षेत्रों में है कब्जे

कर्बला पुल से लेकर मच्छी बाजार तक दोनों तरफ नदी के आसपास अतिक्रमण है। इनमें जवाहर नगर, काटजू कॉलोनी, बारा भाई बस्ती शामिल है। स्वदेशी मिल से भागीरथपुरा बस्ती तक सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुए है। इस बस्ती को प्रशासन ने नोटिस भी दिया है। इसके अलावा कुलकर्णी भट्ट क्षेत्र में भी 300 से ज्यादा कब्जे नदी के दोनों तरफ है।

हाईकोर्ट ने पलटा इंदौर प्रशासन का फैसला, सभी आरोपी रिहा : चावल कालाबाजारी कैसे हुई, आरोपियों को जेल क्यों? इसकी वजह नहीं बता पाए अफसर

इंदौर(एजेंसी)। सरकारी चावल की कालाबाजारी पर एक्शन के एक फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। प्रशासन की कार्रवाई को अवैध मानते हुए आरोपियों को रिहा कर दिया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना कि जिन तथ्यों के आधार पर केस बना, उससे जुड़े सबूत ही प्रशासन के पास अभी नहीं है। दरअसल, मई में प्रशासन ने सैकड़ों बोरी चावल पकड़ा था और इस एक्शन को बड़ा-चढ़ाकर पेश किया था। दावा किया था कि सरकारी चावल को रेहड़ी वालों से खरीदकर बियर और वाइन फैक्ट्री वालों को बेचा जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतीश अग्रवाल, रामप्रसाद गुप्ता और सक्षम अग्रवाल की

खिलाफ रिपोर्ट पेश की। इस पर कलेक्टर ने तीनों को छह महीने के जेल का आदेश दिया था। आरोपी सतीश के वकील मुदित माहेश्वरी ने बताया कलेक्टर के ऑर्डर को आरोपियों ने इंदौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, अब उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने जो दावे किए थे, वह कोर्ट में साबित नहीं कर पाए।

वो 3 कारण, जिस कारण कलेक्टर के आदेश रद्द किया गया

जांच रिपोर्ट बनाने में लापरवाही हुई। कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार को टाइम लिमिट में पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। जो चावल जब्त करना बताया था, वह किस सरकारी राशन दुकान का है, इसका सबूत ही पेश नहीं किया. प्रशासन ऐसी कोई लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया, जिससे साबित हुआ कि चावल सरकारी था।

कार्रवाई के बाद प्रशासन ने यह दावा किया था

अधिकारियों ने तब कहा था कि शासन द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त अनाज लोग रेहड़ी वालों को 10 से 12 रुपए किलो में बेच देते हैं। इनसे छोटे दुकानदार ये चावल खरीदते हैं और उनसे बड़े व्यापारी। ऐसे ही बड़े व्यापारियों से राम प्रसाद गुप्ता और सतीश अग्रवाल ये चावल 20 से 22 रुपए किलो में खरीदकर बियर और वाइन फैक्ट्री वालों को 25 से 27 रुपए किलो में बेचते हैं, जिसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। अधिकारियों ने तब कहा था कि ये दोनों ही पुराने राशन माफिया हैं और दोनों के खिलाफ पूर्व में भी एफआईआर हो चुकी हैं। अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर के आदेश पर एफआईआर सहित अन्य कार्रवाई हुई।

संपादकीय

रेप कांड : मुश्किल में ममता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉ. रेप-मर्डर केस के राजनीतिक रंग लेने और भाजपा तथा समूचे विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए छेड़े सड़क पर संघर्ष के बाद राज्य की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बैक फुट पर दिखाई दे रही है। इसी तनाव में वो कुछ अजीबो गरीब बयान भी दे रही है, जैसे कि पीड़िता का परिवार न्याय नहीं चाहता। या फिर रेप केस में विपक्ष जिस तरह से बंगाल में आग लगा रहा है, वह आग दूसरे राज्यों तक भी फैलेगी वगैरह। इस पर राजनीतिक हल्कों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि कोलकाता रेप कांड के बाद पश्चिम बंगाल में अंगद के पांव की तरह जमी ममता को इससे राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा? इसका बड़ा कारण लंबे समय बाद किसी संवेदनशील मुद्दे पर बंगाल के लोग ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस पूरे मामले में ममता सरकार का रवैया संदेह से भरा और दोषियों को बचाने वाला ज्यादा रहा है। मामले की सीबीआई जांच के बाद हो रहे खुलासों ने यह शक और गहरा कर दिया है। खास कर विपक्षी बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को गरमाया है और ममता से इस्तीफे की मांग कर दी है, उससे ममता चिंतित हैं। वो समझ नहीं पा रही कि भाजपा का मुकाबला कैसे किया जाए। बात यहां तक हो रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता की चिंता का एक और कारण इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों का शामिल होना है। अब तो इसमे स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बीजेपी पीछे उसे हवा दे रही है। कोई भी आंदोलन अगर छात्र आंदोलन में तब्दील हो जाता है तो उसकी मार और गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। विरोध प्रदर्शनों में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो अमूमन राजनीति और ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहते हैं। अगर वो प्रदर्शन में शामिल नहीं है तो आंदोलनकारियों को उनका नैतिक समर्थन हासिल है। ये सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपने पारंपरिक राजनीतिक विरोधियों से निपटना सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लिए आसान है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी शायद यह समझ नहीं पा रही कि यह विरोध प्रदर्शन कहां जाकर थमेगा। पश्चिम बंगाल में इससे पहले नंदीग्राम की घटना के दौरान इस तरह का विरोध देखने को मिला था। लेकिन वह विरोध तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की उद्योगों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की नीति के खिलाफ़ था। इस बार न्याय की मांग में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, समाज में दबी नाराज़गी भी उभरकर सामने आ रही है। भाजपा ने इस मुद्दे को बाद में हाथ में लिया। ममता की परेशानी यह भी है कि यह कांड एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए हुआ है और बचाव में उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि बीजेपी शासित राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं उछाला जाता। राजनीतिक प्रेक्षक इस पूरे मामले को सियासी नफे नुकसान के आईने में देख रहे हैं। बीजेपी अगर इस मुद्दे पर लंबे समय तक आंदोलन चलाने में कामयाब रही तो ममता को मुश्किल हो सकती है। हालांकि यह आसान नहीं है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो ममता उसका पूरा सियासी फायदा उठा लेंगी। इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को कुछ फायदा तो हुआ है, लेकिन उसे आगे की चाल संभल के चलनी होगी। क्योंकि ममता भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हैं।

नजरिया

अनुराग बेहार

लेखक अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ एवं अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर हैं। अंग्रेजी अखबार मिंट में प्रकाशित आलेख से अनुदित

स्कूली माहौल और संस्कृति के मायने

प्रधानाचार्य ने हमें स्कूल का दौरा कराया, जो अच्छी हालत में नहीं था। धूल से भरे प्रयोगशाला के उपकरण, कुछ टूटे हुए कंप्यूटर, बदबूदार शौचालय, वगैरह। यह स्पष्ट नहीं था कि वह हमें क्या दिखाना चाहता था। हम उस शिक्षक की कक्षा में बैठ गए, जिनसे हम वास्तव में मिलने आए थे। उन्होंने छठी कक्षा के बच्चों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाने का शानदार काम किया। कक्षा सवालों और टिप्पणियों से भरी हुई थी। कक्षा समाप्त होने के बाद हमने बातचीत की 'माहौल ही ठीक नहीं है, सर। स्कूल की संस्कृति खराब है', उन्होंने कहा। 'मैं बस कोशिश करता रहता हूँ।'

वह एक छोटे कद का व्यक्ति था, लेकिन उनका सुस्त व्यवहार उसके हट्टे-कट्टे पहलवान की कद-काठी पर भारी पड़ता था। उसकी ऊपर की ओर मुड़ी हुई मूंछें उसकी कर्कश आवाज़ पर नाच रही थीं। 'क्या मुआयना करने आये हैं आप? आप क्या निरीक्षण करने आये हैं?,' उन्होंने पूछा। उनके स्वर की सौहार्दता उनकी उपस्थिति के खतरे को नियंत्रण में रखने के संघर्ष की तरह लग रही थी। 'मुआयना करने नहीं, देखने आए हैं। सुना है यहां के शिक्षक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।' मेरे उत्तर ने उसे हैरान कर दिया। 'यहां शिक्षक बढ़िया काम करते हैं?' यह स्पष्ट नहीं था कि वह किससे पूछ रहा था। फिर उसने कहा, 'अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा।'

फिर उसने खुद को स्कूल में शिक्षक के रूप में पेश किया, और एक क्षेत्रीय-प्रमुख राजनीतिक पार्टी के शहर के विंग के उपाध्यक्ष के रूप में भी। उसने अपने आस-पास बैठे सहकर्मियों को देखा और प्रिंसिपल सहित उनमें से हर एक का परिचय कराया। हम सही-सलामत थे, भले ही थोड़े-बहुत भ्रमित थे- ऐसा लगा कि उनका निष्कर्ष यही था। शायद यही शिक्षकों के अच्छे काम में हमारे विश्वास को समझा सकता है। उन्होंने प्रिंसिपल को हमें कुछ स्थानीय पेड़ खिलाने का निर्देश दिया, फिर घोषणा की कि वे बहुत व्यस्त हैं और चले गए।

प्रधानाचार्य ने हमें स्कूल का दौरा कराया, जो अच्छी हालत में नहीं था। धूल से भरे प्रयोगशाला के उपकरण, कुछ टूटे हुए कंप्यूटर, बदबूदार शौचालय, वगैरह। यह स्पष्ट नहीं था कि वह हमें क्या दिखाना चाहता था। हम उस शिक्षक की कक्षा में बैठ गए, जिनसे हम वास्तव में मिलने आए थे। उन्होंने छठी कक्षा के बच्चों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाने का शानदार काम किया। कक्षा सवालों और टिप्पणियों से भरी हुई थी। कक्षा समाप्त होने के बाद हमने बातचीत की 'माहौल ही ठीक नहीं है, सर। स्कूल की संस्कृति खराब है', उन्होंने कहा। 'मैं बस कोशिश करता रहता हूँ।'

उस दिन सुबह एक अन्य स्कूल में दो महिलाएं एक-दूसरे को गले लगाकर रो रही थीं और मैं आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उनमें से एक उस प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी और दूसरी शिक्षिका। जब हम बातचीत करने बैठे, तो उन्होंने अपने छात्रों की कठिन जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया ङ्क यहाँ ज़्यादातर ईंट भट्ठा मज़दूरों या भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के बच्चे हैं। फिर शिक्षिका ने कहा कि उन्होंने ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति और उन्हें संभालने के तरीके के बारे में सब कुछ प्रिंसिपल से सीखा है। बदले में, प्रिंसिपल ने बताना शुरू किया कि 10 साल पहले इस शिक्षिका के स्कूल में आने के बाद स्कूल में सब कुछ

कैसे बदल गया। तभी भावनात्मक बांध टूट गया। शिक्षक का तबादला दूसरे स्कूल में हो गया था और उसे जल्द ही वहाँ से चले जाना था।

जब वे अपने आपको संभाल पाए, तो उन्होंने वह बात स्पष्ट कर दी जो पहले से ही स्पष्ट थी, कि उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में एक साथ मिलकर इतनी निकटता से काम किया था कि यह कल्पना करना कठिन था कि एक दूसरे के सहयोग के बिना भविष्य कैसा होगा। अध्यापिका दूर के स्कूल में होंगी और यह स्कूल उनके बिना रह जाएगा।

जब हम स्कूल में दाखिल हुए, तभी हम समझ गए थे कि यह एक खुशहाल और साफ-सुथरा स्कूल है। गेट पर हमसे मिलने वाले दो छात्रों ने हमें उत्साह के साथ 'गुड मॉर्निंग' कहा।' और फिर जानना चाहा कि हम किससे मिलने आए हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल के पास भागा और उन्हें बताया कि हम आ गए हैं और दूसरा हमें वहाँ ले गया जहाँ वे थीं। परिचय के बाद, उन्होंने हमें कक्षा तीन की गणित की कक्षा में बैठा दिया। उत्साहित छात्र ब्लैक बोर्ड पर समस्याएं हल करने के लिए एक-दूसरे से आगे निकल रहे थे। फिर उन्हें यह बताना था कि उन्होंने उन्हें कैसे हल किया। किसी भी गलती को छात्र स्वयं सुधारेंगे तथा शिक्षक उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्हें नई समस्याएं विकसित करने में पांच मिनट का समय लगेगा, जिनमें से शिक्षक हल करने के लिए पांच का चयन करेंगे।

चौथी और पाँचवीं की एक संयुक्त कक्षा में, प्रधानाध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। ये छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई 'मज़ेदार नहीं' कहानियों में से किसी एक को आधार बनाकर मज़ेदार कहानियाँ लिख रहे थे। हम वहाँ कुछ देर बैठे रहे, फिर वह हमें अपने दफ़्तर में ले गई जहाँ नोटबुक और छात्रों के प्रोजेक्ट बड़े करीने से रखे हुए थे। ये नोटबुक उन कहानियों की थीं जो उनके छात्रों ने कई सालों में लिखी थीं। उनमें से कई उनके जीवन, उनकी खुशियों और आकांक्षाओं के रिकॉर्ड की तरह थीं, लेकिन हमारे लिए, वे कठिनाइयों को उजागर करने वाली थीं।

उसे अपने मोबाइल पर एक कॉल आया। एक पूर्व छात्रा की शादी होने वाली थी। उसने प्रिंसिपल को फोन किया था क्योंकि उसके पिता जानना चाहते थे कि प्रिंसिपल क्या सलाह देंगे। वह स्नातक छात्रा आठ साल पहले स्कूल से पास हुई थी। उसके पिता के लिए शिक्षक की स्वीकृति प्राप्त करना महत्वपूर्ण था क्योंकि स्कूल इन परिवारों के लिए एक सहारा बना हुआ था। अपने छात्रों के चले जाने के काफी समय बाद भी उसने शिक्षक से सलाह ली और फिर पिता को जवाब दिया।

यह एक साफ-सुथरा और खुशहाल स्कूल था जिसने अपने छात्रों को शिक्षा का तोहफा दिया, लेकिन इससे उन्हें और भी बहुत कुछ मिला। विषय ज्ञान के अलावा, स्कूल ने छात्रों और बड़े समुदाय के जीवन के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया, वरना उनके पास कोई और सहारा नहीं था। यह स्कूल का माहौल था - इसकी संस्कृति।

जिन दो स्कूलों का मैंने दौरा किया, उनके बीच स्पष्ट अंतर स्कूल संस्कृति के सबसे बड़े लेकिन सबसे कम आंके गए स्कूल संस्कृति के निर्धारक को दर्शाते हैं - उसके शिक्षक और उनके बीच के संबंध। सुस्त शिक्षक के स्कूल में ऐसा लगता था कि कोई रिश्ता ही नहीं था, जबकि दूसरे शिक्षक के स्कूल में मुश्किलों के दौर में बनी गहरी दोस्ती थी। इसके असर साफ़ दिखाई दे रहे थे।

हम ऐसे महत्वपूर्ण मामले को संयोग पर नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 में स्कूल संस्कृति और इसके लिए शिक्षकों के बीच संबंधों और टीमवर्क के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करना कठिन है, लेकिन इसमें सीखने के लिए पर्याप्त उदाहरण हैं।

राजनीति

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बंगाल की पूरी सत्ता कठघरे में

वैसे तो पिछले एक महीने में बच्चियों के साथ हुए बर्बर दुष्कर्मों ने पूरे देश को हिलाया है किंतु कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना ने समाज के हर वर्ग को उद्वेलित किया है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध, फिर स्वयं अस्पताल प्रशासन की भूमिका, पुलिस प्रशासन से लेकर पूरी सरकार के व्यवहार ने डर पैदा किया है। शायद पहली बार सुनने में किसी को अतिश्योक्ति लगे इस घटना के आलोक में पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार अपराधियों और माफियाओं के वर्चस्व वाली दिखी है। सत्ता से जुड़ा कोई भी पक्ष मृतका के न्याय के लिए खड़ा होता नहीं दिखा। इसके विपरीत अस्पताल से लेकर सत्ता की संपूर्ण कोशिश मामले में न्याय की गुंजाइश खत्म करने तथा न्याय की मांग करने वालों को धौंस-धमकी व हिंसा से रोकने की रही है। राजधानी दिल्ली के 2012 के निर्भया कांड से तुलना करने वाले कई पहलू की अनदेखी करते हैं। उसमें पीड़िता बस में अकेलेपन की शिकार हुई, निर्जन स्थान पर उसका अर्ध मृत शरीर फेंका गया तथा प्रशासन का व्यवहार ऐसा नहीं रहा जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल को देखा है। उस समय भी सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका किसी तरह मामले को आगे न बढने देने या बड़ा बवंडर से बचने की थी। बावजूद यह नहीं कह सकते कि घटना को दूसरा रूप देने या सप्ताह की निर्लज्ज ताकत से न्याय की मांग को समाप्त करने की रही। ऐसे जघन्य और वीभत्स कांड पर कोई सरकार इस तरह का व्यवहार करें यह कल्पना से परे है।

अस्पताल में करीब 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद महिला डॉक्टर वहां सो रही हो और दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाए तो अस्पताल प्रशासन की पहली भूमिका क्या होनी चाहिए? पुलिस को तुरंत सूचित करना , मामला दर्ज करवाना तथा परिवार को सच्ची जानकारी देकर उन्हें अस्पताल बुलवाना और साथ खड़ा रहना। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसके उलट कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे आत्महत्या साबित करने, परिवार को काफी समय बाद झूठी जानकारी देने और डॉक्टरों की टीमों को अलग-अलग जिम्मेवारी देकर पूरे मामले को खत्म करने का षड्यंत्र किया। लड़की के माता-पिता को आज तक नहीं पता कि बेटी की आत्महत्या करने का फोन किसने किया। अस्पताल में आने के बाद शव देखने के लिए उन्हें 3 घंटे से ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़े और एक व्यक्ति पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं हो तो उनकी क्या दशा हुई होगी इसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना प्राथमिकी के और टीम बनाएं पोस्टमार्ट्म करना और फिर अपने नियंत्रण में ही शव दहन कर देना। इन सबको मिला दीजिए तो दुष्कर्म करने वाले से बड़ा अपराधी अस्पताल प्रशासन दिखेगा। और पुलिस? पुलिस अस्पताल प्रशासन के निर्देशानुसार भूमिका निभाती रही। पुलिस का पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि आरंभ में हमें सूचना क्यों नहीं दी? पोस्टमार्टम के बाद प्राथमिकी क्यों लिखवा रहे हैं? इसके उलट कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर पूरा पुलिस महकमा घटना को रफा-दफा करने में लगा रहा। पुलिस कमिश्नर का वक्तव्य था कि सारा कुछ मीडिया के कारण हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक आवाज उठाने वाले जो संज्ञान में आये पुलिस का त्वरित नोटिस मुकदमा भुगतने को तैयार रहें। इस तरह की धमकी थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान आता था, लेकिन इतना व्यापक नहीं। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध करने वालों के विरुद्ध मोर्चाबंदी की और उन्होंने मार्च कर विरोध भी जताया। तृणमूल कांग्रेस या सरकार के किसी प्रवक्ता ने इसका उत्तर नहीं दिया कि आखिर मुख्यमंत्री किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहीं थीं ? उन्होंने सारी समस्या की जड़ राम और वाम यानी भाजपा और वामपंथी दलों को घोषित कर दिया। उनके राज्यसभा सांसदों ने घटना की आलोचना करते हुए कुछ प्रश्न उठाएं तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ी।

इस तरह चारों तरफ डर और आतंक का वातावरण बनाया गया ताकि कोई विरोध करने का साहस न करे। ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशासन के लिए सीधा संदेश था कि विरोध करने वाले बंगाल में उथल-पुथल मचाना चाहते हैं इसलिए उन्हें हर हाल में रोका जाए। राम करीब 30 प्रतिशत मुसलमानों के लिए संदेश था कि खतरा तुम पर भी है । परिणाम- ऊपर से गांव तक उनके लोग सक्रिय होकर ऐसा वातावरण बनाते रहे कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो। अभी निचले स्तर से समाचार आना शेष है कि कितने लोगों को सरकारी तंत्र का कोपभजन बनना पड़ा है। अलग-अलग विभागों ने पत्र जारी किया कि विभागीय भूमिका से परे कुछ भी अनुशासनहीनता माना जाएगा। स्कूल इंस्पेक्टर के पत्र गए कि स्कूलों में छात्रों की शिक्षा के अलावा कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं होगी। इसी बीच हमने देखा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर न्याय के लिए धरना दे रहे डॉक्टरों पर हिंसक हमले हुए, उन्ह पीटा गया, उनकी सारी व्यवस्था तहस-नहस कर दी गई और अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई। किसी भी न्यायसंगत लोकतांत्रिक धरना या आंदोलन को सुरक्षा देने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है। कानून के विरुद्ध हो तो उन्हें हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का दायित्व भी पुलिस का है। पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो उसे पता होना चाहिए कि इन्हें सुरक्षा न देना आपराधिक कृत्य ही होगा। धरना देने वालों के साथ हिंसा और पिटाई हो रही थी मानो कानून और व्यवस्था का नाम निशान नहीं हो।

जब मुख्यमंत्री ही घटना की संवेदनशीलता को स्वीकार कर मृतका के परिवार के साथ खड़ा होने और न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की जगह विरोधियों के विरुद्ध सड़कों पर उतर जाएं तो यही होता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया तथा मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया तब भी मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 90 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है इसलिए सीबीआई को दो दिनों में मामला पूरा करना चाहिए। उन्होंने चार दिन के अंदर दोषी को फांसी देने तक की भी मांग कर दी। उच्चतम न्यायालय में संज्ञान लेने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ 21 बड़े अधिवक्ता सरकार की ओर से खड़े हैं। उनकी एक दिन की फीस कितनी होगी इसकी कल्पना करिए? आखिर वकीलों की वह टीम क्यों खड़ी हो रही है? क्या मृतका और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने या फिर सरकार के हर व्यवहार की रक्षा करने? अगर ममता सरकार एक छोटा शपथ पत्र उच्चतम न्यायालय में डाल देती कि जो कुछ हुआ वह सरकार को स्वीकार्य नहीं है और न्यायालय जो निर्देश देगा उसका पालन करते हुए सरकार न्याय दिलाने तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी तो वकीलों की इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं करनी पड़ती। अभी तक की छानबीन से पता चल रहा है कि पूरा बंगाल ऐसे ही तंत्र के हाथों है। आईजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल को हटाने के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज को प्रिंसिपल बना देना बता रहा था कि उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के निजी चिकित्सक उनके साथ हैं। अस्पताल में भारी पैमाने पर हर स्तर पर भ्रष्टाचारऔर अपराध के काले कारनामे सामने आ रहे हैं और लगता है जैसे ऊपर से नीचे तक पूरा गैंग इसमें सक्रिय हो जिन्हें कानून का कोई भय नहीं । जिस संजय राय पर कांड का आरोप है वह सिविल वालंटियर है जिसे ममता बनर्जी ने 2011 में शासन में आने के बाद स्थापित किया। यह वैसे ही है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस बनाया। ये वहां पार्टी के लोग माने जाते हैं और इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता तभी तो अस्पताल के अंदर उसकी इतनी बड़ी हैसियत थी। कुल मिलाकर गहराई से देखें तो ऐसा लगेगा कि एक समय अपने ईमानदारी और संघर्ष के लिए जानी जाने ममता मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता के हर स्तर स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन ज्में जकड़े माफियाओं, अपराधियों , भ्रष्टाचारियों के तंत्र की प्रमुख बन गई है और पूरा पश्चिम बंगाल इनके शिकंजे में है।

क्या स्त्री हिंसा के विरुद्ध आंदोलन सियासी है?

मुद्दा

विवेक कुमार साव

लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में शोधार्थी हैं।

यह बात आपको चौंकाने वाली लग सकती है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जिस मुखर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आंदोलन सियासी रूप ले चुका है। यह बात काफी हद तक सही इसलिए भी लगती है क्योंकि जिस रूप में इस आंदोलन की शुरुआत होती है, वह अब उससे बिल्कुल बिखरा-बिखरा नजर आ रहा है। नवान्न अभियान के नाम पर कहीं दुर्गापूजा के पोस्टर फाड़े गये तो कहीं पथराव व आगजनी भी की गयी, इसे हिंसक बनाया गया, हालांकि छात्रों का यह आंदोलन गलत नहीं किंतु जिस रूप में इसे पहुंचा दिया गया, इसपर मंथन करने की जरूरत है। कुछ लोगों का यह सवाल भी है कि इस छात्र अभियान में कितने छात्र मौजूद थे, तृणमूल समर्थकों का मानना है कि छात्र के रूप में आर एस एस के कार्यकर्ता हिंसा फैला रहे थे। भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता के सड़क पर उतरने से सरकार डर गई है। वहीं मंगलवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नवान्न अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई जगहों पर पथराव, लाठीचार्ज, आगजनी की घटना घटी। एक ओर पुलिसकर्मी घायल हुए तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी भी। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पुलिस की करवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह घोषणा की और बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अर्थात बारह घण्टे तक बंगाल बंद रहेगा। वहीं दूसरी ओर अलापन बंधोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल बंद को अवैध बता दिया, इसके बाद से ही सियासी जंग तेज होती चली गयी। यह बात तो अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है कि स्त्री हिंसा के विरुद्ध उठी आवाज की अग्नि में कई पार्टियाँ अपनी रोटी सेंकने की कोशिश में हैं।

एक ओर भाजपा का बंगाल बंद करवाना, दूसरी ओर तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस व जुलूस निकालना, उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच हिंसक झड़प, क्या यह सही मायने में वही हिंसा के विरुद्ध आंदोलन है जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई थी, यह आंदोलन एक विचार की मांग करता है। पूरे बंगाल में हिंसा का तांडव, आपस में मार-पीट, गोली-बम चलाना, क्या इन सब के लिए ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बहन (पीड़िता) के साथ जो हिंसा हुई, उसके न्याय के लिए, क्या बंगाल का एक भाई दूसरे भाई के साथ हिंसा करेगा? आखिर इस हिंसा से किसे फायदा होने वाला है? अगर भाजपा समर्थक सिर्फ स्त्री हिंसा के विरुद्ध न्याय के लिए बंगाल बंद करवा रहे हैं और ममता से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो फिर यही समर्थक पटना, मणिपुर, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में हुई स्त्री हिंसा की घटना के न्याय के लिए कब हड़ताल व आन्दोलन शुरू करेंगे ? कब वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे? खैर ! ममता की छवि पूरे भारत में एक शक्तिशाली नेत्री के रूप में भले ही हो, फिर भी उनकी आलोचना होनी ही चाहिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है, पर हिंसा के बलपर नहीं। पक्ष या फिर विपक्ष दोनों में से किसी का भी हिंसक होना, आम जनता के लिए खतरा का विषय है।

अंततः इन सब के बाद भी मुख्य सवाल बचा ही रह जाता है कि पीड़िता को न्याय कब मिलेगा ?

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हे बुद्धिवीरों! सोशल मीडिया से बाहर निकलो रे

कहा जाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, जैसा भी मिले उसे हड़प-अड़ब लेना चाहिए। पुरातन काल में तो गुरुकुल और मनीषियों के आश्रमों का प्रादुर्भाव शायद इसलिए हुआ था कि वहां ज्ञानार्जन कर अपनी बुद्धि को तेजस्वी बनाया जाए, लेकिन समय का चक्र कुछ इस तरह चला कि गुरुकुल ट्यूशन सेंटर और फिर कोचिंग सेंटर में तब्दील हो गए। गुरुकुल के आचार्य, मनीषी भी धीरे-धीरे टीचर का सफर करते-करते बाद में फैकल्टीज में कब बदल गए। इसके लिए गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ और सांदीपनि की कमेटी इंवेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन मामला पकड़ में नई आ रहा है। कथित 21 वीं सदी में आधुनिक चलित यंत्र के और विकसित वर्शन में सोशल मीडिया का अवतरण क्या हुआ, समूचा विश्व एक जगह एकाकार हो गया। जग एक बिंदु में समाने लगा और मानव पहले से अधिक बुद्धिमान होकर महामानव हो गया। इसी सोशल मीडिया ने महंगे साहित्यिक आयोजनों की वॉट लगा दी और अब साहित्यिक जगत में जूम आयोजन होने लगे और बुद्धिवीरों की पूरी जमात इसमें ऐसे इन्वॉल्व हो गई, जैसे अगर ये सोशल मीडिया न होता तो शायद एक साल में ढेर सारे सम्मान पत्र हासिल नहीं होते। सोशल मीडिया नामक सामाजिक अड्डा ज्ञान का ऐसा केंद्र बन गया है, जिसमें किसी भी इतिहास की टांग तोड़कर हाथ में दे सकते हैं। किसी भी नामी-गिरामी व्यक्ति की साख पर क्वेश्चन मार्क लगाकर उसकी इज्जत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक सकते हैं। इतना ही नहीं अपनी ही बात को इस ब्रह्मांड की सबसे तार्किक बात का गोल्ड मैडल भी दिलवा सकते हैं। इस सोशल मीडिया के बुद्धिवीरों की जमात में कई आशु कवि, व्यंग्यकार, स्तंभकार और स्व घोषित साहित्य मर्मज्ञ के अवतार लेने से ज्ञान की अथाह गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है, जैसे बरसते मानसून में नगरीय निकाय की पोल खोलते विकास की झांकी नजर आती है। उधर, गुरुकुल में भी गुफाओं और कंदराओं में शिक्षार्जन का सिस्टम बना हुआ था तो वर्तमान में भी कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में शिक्षा पर सवाल बारिश ने क्यों खड़े कर दिए? इसके लिए भी बुद्धिवीरों की ताजी जमात ने अपना बुद्धि विलास प्रस्तुत किया हो या न किया हो, लेकिन शासन के सिस्टम ने इस पर संज्ञान लेकर आधुनिक गुरुकुल यानी कोचिंग सेंटर की वे कंदराएं सील करवा दीं और भोले विद्यार्जन करने वाले अब आत्महंता बने हुए हैं। सोशल मीडिया ने भले ही सारे जगत को ज्ञान का अकूत भंडार बख्शा हो, लेकिन वास्तव में अधूरा ज्ञान किसी पिज्जा से कम नहीं होता, जो स्वाद में तो बढ़िया लगता है और उदर में जाने के बाद अपच और अन्य शारीरिक क्रियाओं को जन्म देता है। बुद्धिवीरों की फौज से भरे इस सोशल मीडिया से जब बुद्धिवीर बाहर निकलेंगे तो इस पर हिंदी भी अपनी जान की अमान मांगेगी और नई सोशल मीडियाई हिंदी से मुक्ति मिल जाएगी। अभी ये मैं सोच ही रहा है कि सोशल मीडिया पर नया मैसेज फ्लैश हो गया कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि फलां की वॉट लग जाए। साथ ही परिवार में जितने लोग उनके नाम से उतनी कसमें भी बहती चली आ रही है और मैं इन मैसेजेज डिलीट कर रहा हूं।

संस्कृत सप्ताह विशेष

चेतनादित्य आलोक
वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

संस्कृत का खोया गौरव वापस दिलाना जरूरी

संस्कृत को आधुनिक तकनीक में अपनी क्षमता के लिए भी पहचाना जाता है, विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में और यही कारण है कि आज इसको आधुनिक लोक-जीवन शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कम्प्यूटर की महत्वपूर्ण भाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। संस्कृत भाषा का संरचित वाक्य-विन्यास और व्याकरण इसे कम्प्यूटरकी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए भी उत्कृष्ट बनाता है। अब तो वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में भी इस भाषा के उपयोग की संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं। दरअसल, संस्कृत की संरचना इतनी सटीक है और इसकी ध्वन्यात्मकता इतनी समृद्ध है कि इसे आध्यात्मिक प्रवचन के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना जाता है। आजकल इसे लेकर जर्मनी में अनेक स्तरों पर अनुसंधान-कार्य भी किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक और विराट मारक क्षमता वाले हमारे देशी प्रक्षेपास्त्रों के लिए प्रारंभिक चिंतन का आधार भी संस्कृत में विरचित हमारे वेद एवं उनकी विविध संहिताएं रही हैं।ये वही वेदशास्त्र हैं, जिनसे हमारी महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा आरंभ हुई।यह परंपरा सनातन धर्म की नींव है।संस्कारों की बात करें तो इस वैदिक परंपरा मेंकुल 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार वास्तव में 16 महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, जो आद्योपांत व्यक्ति के जीवन से जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अनुष्ठान जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं।

संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इसे देवताओं की भाषा यानी 'देवभाषा' अथवा 'देववाणी' भी कहा जाता है। अतीत में इस भाषा ने भारतीय सभ्यता को आकार प्रदान किया और आज भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। सच कहा जाए तो संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह अपने आप में ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कार, संस्कृति एवं आध्यात्मिकता का विशाल भंडार समेटे हुए है। संस्कृत भाषा के अत्यन्त विशाल और व्यापक भंडार में गद्य, पद्य एवं चम्पू तीनों रूप मौजूद हैं। संस्कृत के इस महाभंडार में विश्व के प्रथम ग्रन्थ 'ऋग्वेद' समेत चारों वेद, समस्त उपनिषद, श्रीमद्भाग्वत महापुराण सहित अट्ठारहों पुराण, अत्यंत लोकप्रिय तथा सनातन संस्कृति एवं सभ्यता के निरूसीम प्रामाणिक विस्तार वाली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महान ग्रंथ श्रीरामचरित मानस तथा श्रीराम कथा का प्रामाणिक आधार ग्रंथ महर्षि वाल्मिकी कृत रामायण, स्मृतियां, सूक्त, त्रयीसंग्रह, धर्मशास्त्र, महाभारत एवं अन्य कई महाकाव्य, नाटक आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष, वेदांग-न्याय, वैशेषिक सांख्य योग, वेदांग मीमांसा, दर्शन आदि इसी भाषा की देन हैं। दर्शनों में हिंदू, जैन, बौद्ध, चार्वाक, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

रचनाकारों में अगस्त्य, अमरु, असाग, अश्वघोष, आर्यशूर, वाल्मीकि, व्यास, भल्लट, भवभूति, भीमस्वामी, भूवनदेव, मंखक, दंडी, भास, भारवि, कल्हण, कौटिल्य, कुंतक, सुबन्धु, माघ, बाणभट्ट, कालिदास, रत्नाकर स्वामी, श्रीहर्ष, जल्हण, जयदेव, शूद्रक, विशाखदश्र, लोलिम्बराज, विष्णु शर्मा, सत्यव्रत शास्त्री, हर्ष, राजशेखर एवं हर्षवर्धन आदि कवि, नाटककार, गद्यकार तथा पाणिनि जैसे अनन्य व्याकरणविद् संस्कृत भाषा के गरिमामय भंडार के महत्वपूर्ण अंग हैं। गौरतलब है कि संस्कृत भाषा के गर्भ से अनेक देशी एवं विदेशी भाषाओं का जन्म होने के कारण इसे 'भाषाओं की जननी' भी कहा जाता है। हालांकि पिछली सदियों में संस्कृत भाषा और इसमें रचित साहित्य तथा इसे रचने वाले साहित्यकारों को बहुत उपेक्षाएं झेलनी पड़ीं, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही और आज भी कायम है, जबकि लैटिन एवं ग्रीक सहित दुनिया की दूसरी कई भाषाएं उपेक्षित होकर समय के तीव्र प्रवाह में काल-कवलित हो गयीं। संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता बनी रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली इस भाषा की वर्तनी, वर्ण, अक्षर तथा इनसे बनने वाले शब्दों के उच्चारण में आभासी अन्तर बिल्कुल नहीं होता। तात्पर्य यह कि संस्कृत एक सुनिश्चित व्याकरण वाली पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है।

संस्कृत को आधुनिक तकनीक में अपनी क्षमता के लिए भी पहचाना जाता है, विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में और यही कारण है कि आज इसको आधुनिक लोक-जीवन शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कम्प्यूटर की महत्वपूर्ण भाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। संस्कृत भाषा का संरचित वाक्य-विन्यास और व्याकरण इसे कम्प्यूटरकी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए भी उत्कृष्ट बनाता है। अब तो वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में भी इस भाषा के उपयोग की संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं। दरअसल, संस्कृत की संरचना इतनी सटीक है और इसकी ध्वन्यात्मकता इतनी समृद्ध है कि इसे आध्यात्मिक प्रवचन के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना जाता है।आजकल इसे लेकर जर्मनी में अनेक स्तरों पर अनुसंधान-कार्य भी किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक और विराट मारक क्षमता वाले हमारे देशी प्रक्षेपास्त्रों के लिए प्रारंभिक चिंतन का आधार भी संस्कृत में विरचित हमारे वेद एवं उनकी विविध संहिताएं रही हैं। ये वही वेदशास्त्र हैं, जिनसे हमारी महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा आरंभ हुई। यह परंपरा सनातन धर्म की नींव है। संस्कारों की बात करें तो इस वैदिक परंपरा में कुल 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार वास्तव में 16 महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, जो आद्योपांत व्यक्ति के जीवन से जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अनुष्ठान जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं।

इन संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण 'उपनयन संस्कार' माना जाता है, जो कि दसवां संस्कार होता है। यह अनुष्ठान प्राचीन काल से ही बच्चों की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक रहा है। यह सावन पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, जब संस्कृत में 'गायत्री मंत्र' के पाठ के साथ बच्चों को वैदिक शिक्षा की दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के प्रवेश का प्रतीक होती है, जो व्यक्तियों के शैक्षिक और आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करती है। संस्कृत भाषा की इन्हीं विशेषताओं एवं उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए इसको सम्मान एवं संरक्षण देने तथा इसके पुनरुत्थान के उद्देश्य से लगभग 55 वर्ष पूर्व सन् 1969 की 'सावन पूर्णिमा' को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर पहली बार कृतज्ञ राष्ट्र ने 'संस्कृत दिवस' मनाया था। इस बेहद महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए सावन पूर्णिमातिथि के चयन का प्रमुख कारण यह है कि प्राचीन काल में भारतवर्षके समस्त अध्ययन केंद्रों में शिक्षण-सत्र का शुभारंभ सावन पूर्णिमा के शुभ दिन को ही शुभ मुहूर्त में किया जाता था। यह शिक्षण-सत्र अगले वर्ष पौष पूर्णिमा तक चलता था और प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा से सावन पूर्णिमा तक देश भर के सभी अध्ययन केंद्र बन्द रहते थे।

शिक्षण-सत्र का शुभारंभ हंसी-खुशी, उमंग और उत्सव के माहौल में वेद एवं अन्य शास्त्रों के पाठ के साथ किया जाता था। कमोबेश उसी परंपरा को मानते हुए सन् 1969 से लेकर आज तक प्रायः प्रत्येक वर्ष 'सावन पूर्णिमा' को भारत सरकार संस्कृत दिवस का आयोजन करती आ रही है। इसके अतिरिक्त देश भर की राज्य सरकारें शिक्षण संस्थान एवं अध्ययन केंद्र भी संस्कृत दिवस का आयोजन करते हैं।इस दिन राज्य एवं जिला स्तरों पर संस्कृत भाषा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कवि-सम्मेलनों के अतिरिक्त लेखकों तथा आचार्यों की संगोष्ठियां भी शामिल होती हैं। स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच भाषण एवं 'श्लोक-पाठ' प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संस्कृत भाषा के उत्थान को लेकर मनीषी राजनेता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान सन् 2000 में 'संस्कृत सप्ताह'के आयोजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी।हालांकि इस प्रकार की औपचारिकताएं निभाने मात्र से संस्कृत भाषा का कल्याण नहीं होने वाला। इसके लिए तो जरूरी है कि देश भर में अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को रोका जाए, साथ ही, उसके प्रभाव एवं वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया जाए।इसके अतिरिक्त उपेक्षा, अवमानना और विरोध का दंश झेलती तथा सतत संघर्ष करती आ रही देवभाषा संस्कृत के पुनरुत्थान एवं प्रचार-प्रसार के लिए समुचित प्रयास किए जाने की भी जरूरत है। यदि वास्तव में ऐसा किया गया तो देश में संस्कृत पढ़ने, लिखने और बोलने वालों की संख्या में वृद्धि होगी तथा संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ सम्मान एवं गौरव पुनः प्राप्त हो सकेगा।

हालांकि संस्कृत की प्रासंगिकता अब प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंगभीबन चुकी है, विशेष रूप से भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत। दरअसल, संस्कृत भाषा की अपरिहार्यता और इसके महत्व को पहचानते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत की भूमिका को और स्पष्ट एवं सशक्त करने का कार्य किया है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों और दर्शनों के अध्ययन पर जोर दिया गया है, जो मुख्य रूप से संस्कृत में ही रचित और उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को समेकित रूप से शामिल करने पर जोर देती है, जिसमें संस्कृत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उक्त शिक्षा नीति के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा, समकालीन विद्वानों और प्राचीन भारतीय ज्ञान के विशाल भंडार के बीच संस्कृत एक सेतु के रूप में कार्य करती है।

सरोकार

राजेन्द्र जोशी
स्वतंत्र पत्रकार

नर्मदा घाटी में समाधान नहीं, आश्वासन मिला

सरदार सरोवर डेम की जद में आये मप्र सहित महाराष्ट्र व गुजरात के प्रभावितों की तुलना की जाए तो मप्र को छोड़कर दोनों राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर बेहतर पुनर्वास हुआ है, लेकिन मप्र में यह सब नहीं हो पाया है। और इसी के चलते यहां के सैकडों प्रभावित आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरदार सरोवर बांध में पानी भरने की क्षमता 138.68 मीटर है। बीते सालों में इस स्तर पर पानी भरा जा चुका है, वही बांध की वजह से बैकवाटर का लेवल अलग अलग स्थानों पर अलग रहा है जो कि 141 से 146 मीटर तक का रहां है। यह स्तर गांव-गांव सर्वे के आधार पर तय किया गया था, और उसी आधार पर डूब प्रभावितों के लिये मुआवजा राशि व पुनर्वास राशि तय की गई थी।

साल दर साल पूरे पचास बरसों से अधिक समय की मांगें और 40 बरसों से नर्मदा घाटी के लोगों के बेहतर पुनर्वास,उचित मुआवजे की दरकार के साथ अनिमियतताओं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सहित अनेक मांगों को लेकर नर्मदा घाटी में चल रहे आंदोलन में प्रभावित परिवारों की तीन-तीन पीढ़ियां खप गई है,लेकिन उनकी समस्या का समाधान आश्वासन ही रहा है। सत्ता बदली है, लेकिन सरकार (अधिकारी कर्मचारी) तो वही हैं।

सरदार सरोवर डेम की जद में आये मप्र सहित महाराष्ट्र व गुजरात के प्रभावितों की तुलना की जाए तो मप्र को छोड़कर दोनों राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर बेहतर पुनर्वास हुआ है, लेकिन मप्र में यह सब नहीं हो पाया है। और इसी के चलते यहां के सैकड़ों प्रभावित आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरदार सरोवर बांध में पानी भरने की क्षमता 138.68 मीटर है। बीते सालों में इस स्तर पर पानी भरा जा चुका है, वही बांध की वजह से बैकवाटर का लेवल अलग-अलग स्थानों पर अलग रहा है जो कि 141 से 146 मीटर तक का रहां है। यह स्तर गांव-गांव सर्वे के आधार पर तय किया गया था, और उसी आधार पर डूब प्रभावितों के लिये मुआवजा राशि व पुनर्वास राशि तय की गई थी।

प्रारम्भिक सालों में यह व्यवस्था सुचारू रही। बाद में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के चलते पुनर्वास और मुआवजा लालफीताशाही की भेंट चढ़ गया। बाद के सालों में पुनर्वास और मुआवजे से सैकड़ों लोगों के मामले न्यायिक प्राधिकरण में आज भी लम्बित है। इन्हीं के बीच कम मुआवजे और अन्य कारणों से लाभ ले चुके प्रभावितों के मामले भी प्राधिकरण में है। इन प्रकरणों में पारिवारिक विवाद,नियम विरूद्ध दिये गये मुआवजे, कम मुआवजे के साथ डूब से बाहर किये गये प्रभाविते के मामले लम्बित है। इन्हीं प्रभावितों में ऐसे कई परिवार है जिन्हे आज तक कुछ भी नहीं मिला,जबकि उसके पड़ोसी को या गांव फल्ये वाले को समुचित लाभ मिल गया है,और इसके पीछे जो कारण सामने आया है वह है बैकवाटर लेवल को कम करने का खेल नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा बिना सर्वे के ही एक से लगाकर तीन मीटर तक का बैकवाटर लेवल कम करके कई परिवारों को डूब से बाहर कर दिया जबकि उसी गांव के कई प्रभावितों को पूर्व में मुआवजा मिल चुका है। जिन गांवों को डूब के सर्वोच्च लेवल 138.68 से बाहर रखा गया था एवं कहा गया था, आपके यहां पानी नहीं आयेगा वैसे कई गांवों में सितम्बर 2023 की 16 व 17 तारीख को वाटर लेवल बताये लेवल से कई गुना ऊपर पहुंचा और पूरे गांव की करोड़ों कर चल अचल सम्पत्ति बह गई,उन्ही में से धार जिले की मनावर तहसील का एकलबारा ग्राम भी रहां है।नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की लापरवाही के चलते पूर्ण मुआवजा लेने वाले कई ग्रामवासी आज भी मूल ग्राम में बसे हुये और उनके लिये बनाये गये पुर्नवास स्थल की जमीने आज भी जस की तस पड़ी हुई है। सितम्बर 2023 की बाढ़ और बैकवाटर में खरगोन के नावडाटौली,बडवानी जिले के ब्राहम्णगांव, खेड़ी धार जिले के धरमपुरी कोठड़ा सहित अनेक गांव है जिन्हे सालों पहले मुआवजा मिल चुका है,लेकिन वे पुर्नवास स्थलों पर नहीं गये, सितम्बर की बाढ़ के बाद धरमपुरी के प्रभावितों ने पुनर्वास स्थल पर निर्माण प्रारम्भ कर दिये है,कुछ रहने भी चले गये है तो कुछ व्यापारिक कारणों से वहीं पर रह रहे है। वहीं दूसरी और सम्पूर्ण पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के लिये बनाये गये स्थल, पंचायत भवन,सामुदायिक स्वास्थ केंद्र,उपासना स्थल, सड़कें, ड्रेनेज व्यवस्था खस्ताहाल में पहुंच चुकी है, जबकि किसी भी नई बसाहट या कालोनियों के विकास को हम देखते है तो ऐसा लगता है पुनर्वास स्थल भी ऐसे होंगे लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर है। इन पुनर्वास स्थलों में जिन प्रभावितों को समतल जमीनें मिल गई वे किस्मत के धनी निकले,नहीं तो कई लोगों के मुआवजे की राशि अपने प्लाट का लेवल करने में ही समाप्त हो गई। वर्तमान समय में संभाग स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के नर्मदा घाटी के भूअर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों में अधिकारी तक नहीं है, सरकार राजस्व अधिकारियों से काम करवा रही है, इसी के चलते प्रभावितों के छोटे बड़े सभी कार्य प्रभावित हो रहे है, विशेषकर मानसून सत्र में।

युद्ध विरोधी दिवस पर विशेष

सुरेश उपाध्याय

युद्धों से जूझती दुनिया और युद्ध विरोधी दिवस

पहले व दूसरे विश्व युद्ध में क्रमशः दो करोड़ व पांच करोड़ लोगों के मारे जाने तथा हिरोशीमा व नागासाकी में अणु बम से महाविनाश के बाद भी दुनिया ने कोई सबक नहीं सीखा है. एक सितम्बर 2024 को जब हम युद्ध विरोधी दिवस मना रहे है तो विश्व के समक्ष दो बडे युद्ध चुनौती बने हुए हैं. रुस - यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है तथा ढाई वर्ष के इस काल मे नागरिक ठिकानो, स्कूलो, अस्पतालो को भी निशाना बनाया गया है तथा मासूम बच्चे, निरपराध नागरिक मारे गए है. महिलाओं के उत्पीड़न, 80 लाख लोगों के शरणार्थी बनने की विवश्ता के साथ पावर ग्रीड पर हमले, साइबर वार फेअर आदि हाइब्रीड युद्ध के तत्वों का प्रयोग भी हुआ है. सोवियत संघ के बिखराव के बाद वारसा संधी तो समाप्त हो गई लेकिन नाटो का विघटन करने के बजाए विस्तार किया गया है. इस युद्ध के मूल का यही एक कारण है. 2008 में यूक्रेन व जार्जिया ने नाटो का सदस्य बनने की मांग की जिसका पश्चिमी यूरोपीय देशो ने विरोध किया लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने दबाव बना कर साम्राज्यवादी मंसूबों का इजहार किया था. 2014 में क्रीमीया पर रुस के कब्जे के बाद कुछ नाटो सदस्यों ने यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरु किया था. अमेरिका सहित नाटो के कई सदस्य यूक्रेन को सैन्य सामग्री, हथियार आदि प्रदाय कर रहे हैं और परोक्ष सहयोगी की भूमिका में हैं. ऐसे में नाटो के रुस की सीमा तक पहुंचने की चिंता स्वाभाविक कही जा सकती है. रुस-चीन की नजदीकियों से एकल ध्रुवीय व्यवस्था को मिल रही चुनौती भी सम्भवतः इसके मूल में हो सकती है.

दूसरी ओर इजरायल - फिलिस्तीन युद्ध अक्टूबर 2023 से जारी है तथा दस माह से जारी इस युद्ध में बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध किए गए है. स्कूल, अस्पताल, नागरिक ठिकानों पर हमले में मासूम बच्चे, निरपराध नागरिक मारे गए है, 50 लाख लोग शरणार्थी बनने को विवश हुए हैं, महिलाओं के यौन शोषण व उत्पीड़न के प्रकरण सामने आए हैं. यरुशलम तीन धर्मो (यहूदी, इस्लाम व ईसाई) के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा झगड़े के मूल में इस पर दावा व कब्जे के प्रयास हैं, जो उन्नीस वीं सदी के आखरी दशक से घनीभूत माने जाते है. 29 नवम्बर 1947 को सन्युक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और यरुशलम शहर में विभाजित करने और लागू करने की सिफारिश की थी. 1948 में इजरायल की स्थापना हुई और उसने विस्तार के प्रयास किए तथा छुटपुट संघर्ष होते रहे हैं. 1964 में यासेर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की शुरुआत हुई थी. 1967 के 6 दिवसीय अरब- इजरायल युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, गाजापट्टी, मिस्त्र के सिनाई, सीरियाई गोलान हाइट्स और अकाबो की खाड़ी के दो द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहल पर फिलिस्तीन और अरब देशों द्वारा इजरायल को मान्यता के बदले कब्जाए क्षेत्र से वापसी और वेस्ट बैंक व गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना व शरणार्थियों का न्यायसंगत समाधान शामिल था. शांति के लिए भूमि और दो राज्य समझौते के माध्यम से फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सन्युक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया था. 2006 में अतिवादी संगठन हमास ने चुनाव जीता और इजरायल ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे. फतह और हमास के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष के बाद 2007 में हमास ने गाजापट्टी के पुरेक्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था. हमास नियंत्रित गाजा से इजरायल पर तथा इजरायल से गाजा पर छुटपुट राकेट हमले होते रहे थे. 2022 में इजरायल में कट्टरपंथी नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसके बाद इजरायल में अधिक राजनीतिक संघर्ष हुए और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में झड़पे तेज हुई थी. इसकी परिणिति 2023 के हमास-इजरायल युद्ध में हुई है. हमास के हमले से 1200 से अधिक इजरायली नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए तथा कुछ बंधक बना लिए गए थे.

तत्पश्चात इजरायल के हवाई और जमीनी हमलों से अनेक बेकसूर नागरिक व बच्चे मारे गए हैं. हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद युद्ध के विस्तार की सम्भावनाए बढ़ी है.

अभी इन दोनों युद्धों पर विराम की सम्भावनाएं दिखाई नहीं दे रही है. किसी भी युद्ध में दो देश की सेनाएं व सरकारें ही प्रभावित नहीं होती है, अवाम के संकट और गहराते हैं. इसके साथ ही पूरी दुनिया के देशों में अलग अलग तरह के संकट उत्पन्न होते हैं, जैसे रुस-यूक्रेन युद्ध से अनेक देशों में खाद्यान्न, प्राकृतिक गैस व तेल का संकट हुआ है तथा अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष नई चुनौतिया आई है. आज के युग में युद्ध से फायदा हथियार निर्माताओं, हथियारों के व्यवसाय पर निर्भर साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ही होता है. निरपराध नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओ के गौरव व सम्मान, शरणार्थियों की समस्याओं से निजात व मासूम बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व खुशहाल भविष्य के लिए इन दोनों युद्धों पर तत्काल रोक लगना चाहिए. हथियारों की होड़ पर रोक. नाटो का विघटन, फिलिस्तीन की स्वायत्ता व आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा, आणविक / जैविक / रासायनिक हथियारों के जखीरों को क्रमशः नष्ट करना तथा और अधिक घातक हथियारों के अनुसंधान पर रोक ही मनुष्य की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा. 2024 के युद्ध विरोधी दिवस पर यही संकल्प होना चाहिए.

संक्षिप्त समाचार

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल जीवन मिशन का किया जा रहा है प्रचार-प्रसार

रायसेन (निप्र)। जिले के सांची जनपद के ग्रामों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रचार रथ द्वारा तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल जीवन मिशन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में सांची जनपद के दीवानगंज में ग्रामीणों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को जल जीवन मिशन के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शुद्ध पेयजल और जल संरक्षण हेतु जागरूक किया गया। साथ ही जल जीवन मिशन के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

आंगनवाड़ी के बच्चों के लिये बैग, स्लेट, बुक्स व पेंसिल भेंट की

हरदा (निप्र)। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिये एलडीएस ग्रुप के सदस्यों ने उपहार भेंट किये। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि रहटाखुर्द आंगनवाड़ी केन्द्र में मंगलवार को एलडीएस ग्रुप के सदस्यों ने बच्चों के लिए बैग, स्लेट, बुक्स, पैन, पैंसिल व बिस्किट के पैकेट तथा हरदा शहर के वार्ड क्रमांक 2 के आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर व बिस्किट वितरित किए।

पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 सितम्बर को लगेगा रोजगार मेला

हरदा (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी श्री लक्ष्मणसिंह सिलोटे ने बताया कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में 4 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में बाहरी एवं स्थानीय कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षुकर्मी, मशीन ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिल्ड ऑफिसर, बीमा अभिकर्ता सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष की आयु के 5वी., 8वी, 10वीं, 12वीं, स्नातक व आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते है। श्री सिलोटे ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकसूची, निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साइज के 4 फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि व समय पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में उपस्थित होकर रोजगार मेले का लाभ प्राप्त कर सकते है। मेले में भाग लेने के लिये कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं होगा। रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नम्बर 07577-223655 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर श्री सिंह ने तेली की सराय परिसर में पौधरोपण किया

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने तेली की सराय परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस दौरान उन्होने तेली की सराय पर्यटन स्थल पर लाइट एण्ड साउण्ड शो जैसी गतिविधि शुरू करने तथा आने वाले पर्यटकों के लिये सुविधाएं बढ़ाने के लिये कहा। उन्होने तेली की सराय पहुँच मार्ग की दशा सुधारने तथा परिसर में स्ट्रीट लाइट बढ़ाने और चौकीदार की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिये। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री रोहित सिसोनिया, गांव की सरपंच व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले पक्के आवास ने मेरे आशियाने के सपने को साकार किया

रायसेन (निप्र)। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के स्वयं के पक्के मकान के सपने को साकार करने का काम कर रही है। रायसेन निवासी श्रीमती प्रियंका रजक भी उन हितग्राहियों में शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले पक्के आवास ने मेरे आशियाने के सपने को साकार किया। बीते दिनों को याद करते हुए वह कहती है कि कच्चे मकान में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पक्का आवास मिलने से बारिश में सीलन भरे कच्चे मकान से मुक्ति मिल गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूल, अस्पताल, गौशाला व छात्रावासों का किया निरीक्षण

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने बुधवार को जिले के ग्राम बागरूल स्थित दिव्यांग छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होने छात्रावास पहुँच मार्ग सुधारने के लिये जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये छात्रावास के बाहर स्थित भूमि पर खेल मैदान तैयार कराने के निर्देश भी जनपद सीईओ हरदा को दिये। विद्यार्थियों ने कलेक्टर श्री सिंह को बताया कि होस्टल का टीवी खराब पड़ा है, जिसे सुधरवाने के निर्देश उन्होने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होने छात्रावास के पास ही स्थित डाइट परिसर में बने शासकीय आवासों की रिपेयरिंग कराकर उन्हें शासकीय कर्मचारियों को आवंटित करने के निर्देश भी डाइट प्राचार्य को दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने बागरूल में डाइट परिसर में स्थित आजीविका परियोजना के प्रशिक्षण केन्द्र भवन में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिये। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री रोहित सिसोनिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। छात्रावास में केरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करें और पुस्तकालयों में उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराएं

कलेक्टर श्री सिंह ने हॅंडिया के अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का भी निरीक्षण किया। उन्होने होस्टल परिसर में सी.सी. टीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने तथा क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी कर्मचारियों के फोन नम्बर सूचना पटल के पास अंकित कराने के निर्देश दिये ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी अपनी समस्या बता सकें। उन्होने उपस्थित छात्राओं से चर्चा कर समस्याएं भी सुनी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये छात्राओं को उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। उन्होने हायर सेकण्ड्री की छात्राओं के लिये केरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी जिला संयोजक को दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास पहुँच मार्ग पर कीचड़ और गंदगी देखकर नाराजगी प्रकट की और मार्ग की रिपेयरिंग के निर्देश दिये। उन्होने बीआरसी और जनपद के सीईओ को छात्रावासों का हर सप्ताह नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये।

गौशाला परिसर में सी.सी. टीवी कैमरे लगाएं

कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम हीरापुर में गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होने गौशाला परिसर में प्रतिदिन एकत्र होने वाले गोबर व गौमूत्र से गौकाष्ठ और अन्य उपयोगी सामग्री तैयार कर गौशाला की आय बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होने गौशाला के पशुओं के लिये चारागाह की भूमि उपलब्धता की भी जानकारी ली तथा गौशाला परिसर में सी.सी. टीवी कैमरे लगाने और चौकीदार की नियुक्ति करने के लिये उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को निर्देशित किया।

अजनास रैयत में पेयजल योजना का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री सिंह ने भ्रमण के दौरान ग्राम अजनास रैयत में जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल जल योजना का निरीक्षण किया।

सोनतलाई में अस्पताल और स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार के दिये निर्देश

कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम सोनतलाई स्थित हायर सेकण्ड्री स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होने स्कूल परिसर में अव्यवस्थाओं के लिये प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने स्कूल परिसर में स्थित कम्प्यूटर लेब और लेबोरेटरी का भी निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश प्राचार्य को दिये। ग्राम सोनतलाई में कलेक्टर श्री सिंह ने आंगनवाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया और आंगनवाड़ी भवन की छत की रिपेयरिंग कराने के निर्देश पंचायत सचिव को दिये। उन्होने सोनतलाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया और अस्पताल में चौकीदार व सफाई कर्मी की व्यवस्था करने के निर्देश ग्राम पंचायत के सचिव को दिये। उन्होने तहसीलदार को निर्देश दिये कि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री का भौतिक सत्यापन करें।

इस दौरान उन्होने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री पवनसुत गुप्ता को निर्देश दिये कि नल जल योजना की पाइप लाइन बिछाने के लिये जो सड़कें खोदी गई है, उनकी तुरन्त रिपेयरिंग करायें ताकि बरसात में ग्रामीणों को होने वाली असुविधा से मुक्ति मिल सके।

कलेक्टर श्री दुबे ने राजस्व महाअभियान 2.0 की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की जिला स्तरीय बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी लेते हुए विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से कहा कि सरकार द्वारा किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए राजस्व महाअभियान 2.0 की समयावधि 31 अगस्त तक निर्धारित की गई है। सभी राजस्व अधिकारी आगामी तीन दिवसों में राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री दुबे ने राजस्व अधिकारियों से नामांतरण, बंटवारा, सीमाकंन, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शा तरमीम प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए प्रतिदिन की कार्यप्रगति से अवगत कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समग्र ई-केवायसी, पीएम किसान ईकेवायसी, स्वामित्व योजना एवं राजस्व वसूली पर भी विस्तार से चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की भी जानकारी लेते हुए नियमानुसार निराकरण किए जाने के निर्देश दिए।

दंत-शक्ति अभियान के तहत स्कूलों में हुआ दंत परीक्षण

हरदा (निप्र)। ओरल हेल्थ प्रमोशन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता लाने व अच्छी आदतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कलेक्टर आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप ''हरदा दंत-शक्ति अभियान'' प्रारंभ किया गया है। अभियान के तहत जिले में बच्चों के दांतों की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि अभियान के तहत बुधवार को जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में बच्चो के दांतों की जांच की गई। दंत चिकित्सक डॉ पियूष दोगने, डॉ. जॉनसन, डॉ. निकिता माहेश्वरी, डॉ. काजल अग्रवाल, डॉ. मंजू वर्मा, डॉ. परमानंद छलोत्रे, डॉ. मीनाक्षी चौरसिया ने बच्चों के दांतों की सामान्य जॉच की व टूथ ब्रश करने का सही तरीका भी बताया।डॉ. सिंह ने बताया कि अभियान के तहत जिले की सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 5 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के 26523 बच्चे अब मध्यान्ह भोजन करने के बाद फ्लोराईड युक्त टूथ पेस्ट ब्रश करेंगे। जिले के सभी प्राथमिक शालाओं तक ओरल हेल्थ सामग्री पहुंचाई गई है। सीएमएचओ डॉ. सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के लिए जिले की 530 प्राथमिक शाला के शिक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी छह माह तक चलने वाले दंत-शक्ति अभियान में हर दो माह में बच्चों की दांतों की जॉच की जाएगी तथा विशेष शिविर लगाकर चिन्हित बच्चों को दंत क्षय, प्लाग, मसूड़ो की समस्या का उपचार भी दिया जावेगा। उन्होने बताया कि प्रति सोमवार, बुधवार और शनिवार को जिले की सभी प्राइमरी स्कूलों में स्वास्थ्य दल द्वारा जांच की जावेगी ।

बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रही लाड़ली बहना योजना

सीहोर (निप्र)। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार दो सौ पचास रूपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। जिसे महिलाएं अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर रही है। सीहोर निवासी श्रीमती रानी यादव भी लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं में से एक है। श्रीमती रानी बतातीं हैं कि लाड़ली बहना योजना से मुझे जो राशि मिली है, उसे मैं अपने बच्चों एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग कर रही हूं। उन्होंनें बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है।

सभी लक्षित बच्चों को कृमि नाशक एल्बेडॉजाल टेबलेट खिलाने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

सीहोर (निप्र)। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 सितम्बर के अवसर पर जिले के सभी लक्षित बच्चों को कृमि नाशक एल्बेडॉजाल टेबलेट दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष मे बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने 10 सितम्बर को सभी शैक्षिणक संस्थानों में एल्बेडॉजाल टेबलेट उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को समान्वय कर सभी लक्षित बच्चों को टेबलेट खिलाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों, अशासकीय शालाओं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिले में 5 लाख 65 हजार 720 बच्चों को कृमि नाशन टेबलेट एल्बेडॉजाल खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष आयु के लक्षित सभी बच्चों, किशोर, किशोरियों, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को यह दवा खिलाई जाएगी। अभियान के अंतर्गत आष्टा में 1 लाख 54 हजार 585, बुधनी में 60 हजार 283, इछावर 69 हजार 702, भैरूंदा 94 हजार 592 तथा सीहोर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 86 हजार 558 लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमि नाशन की दवा खिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि एल्बेंडॉजाल की गोली 01 से 02 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 400 मि.ग्रा. की आधी गोली पानी के साथ खिलाई जाएगी। 2 से 3 वर्ष आयु वर्ग व 3 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों किशोर किशोरियों को एल्बेंडॉजाल की 400 मि.ग्रा.की पूरी गोली खिलाई जाएगी। अभियान के दौरान सेवा प्रदाता मैदानी कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी, ए.एन.एम., आशा पर्यवेक्षक, शालाओं में शिक्षकों के द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार कृमि नाशन की दवा दी जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपुत,श्री नितिन टाले,श्री आनंद सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्या है कृमि

कृमि ऐसे परजीवी हैं जो व्यक्ति के आंत में रहते हैं और जीवित रहने के लिए मानव शरीर के जरूरी पोषक तत्व को खाते हैं। जिसके कारण एनीमिया, कुपोषण, और मानसिक, और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती हैं। संक्रमित बच्चे अक्सर, स्कूल जाने के लिए बहुत थके हुए या बीमार होते हैं। आंतों के कृमि संक्रमण से हर साल 200-524 मिलियन स्कूली बच्चों की शिक्षा का नुकसान होने का अनुमान है। व्यस्क होने पर आर्थिक विकास के लिए कृमि, गंभीर खतरे पैदा करते हैं। हुकवर्म के गंभीर संक्रमण से आयु में 43 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। कृमि नाशन से समुदाय में कृमि की व्यापकता में कमी लाई जा सकती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, एनीमिया का नियंत्रण, सीखने की क्षमता और कक्षा में उपस्थिति में सुधार, व्यस्क होने पर काम करने की क्षमता और आयु में बढ़ोत्तरी होती है।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार मिशन शक्ति योजना के तहत संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा 21 जून से से 4 सितंबर तक महिला केंद्रित विषयों पर 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। जिसके तहत जिले में ब्लाक परियोजना सेक्टर आंगनवाडी तथा विद्यालय स्तर पर विभिन्न शिविर पंजीयन अभियान, सार्वजनिक बातचीत कार्यशालाए, सेमीनार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष आउटरीच साप्ताहिक गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है।

संकल्प-हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन डीएचईडब्ल्यू द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा तथा लिंगानुपात को बढ़ाने, जन समुदाय को जागरूक करने और उन्हे कौशल विकास की जानकारी देने के उद्देश्य से शासकीय स्वामी विवेकानंद हायर स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विधायक श्री टण्डन ने हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षण हेतु किसानों को रवाना किया

जिले के तीस प्रशिक्षक राजगढ़, शाजापुर, सीहोर में उद्यानिकी फसलों से प्रशिक्षित होंगे

विदिशा (निप्र)। उद्यानिकी विभाग की किसानो के प्रशिक्षण संबंधी योजना के तहत जिले के चयनित तीस कृषक उद्यानिकी फसलों से प्रशिक्षित होने हेतु रवाना हुए है। विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने कलेक्टेऊट परिसर में उद्यानिकी फसलों के प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु रवाना होने वाले कृषक दल के सदस्यों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे पहले विधायक श्री टण्डन ने किसानो से संवाद कर उन सबसे कहा है कि उद्यानिकी क्षेत्र में अन्य जिलो में हुए नवाचारो को देखकर, सुनकर, सीखकर, उसका उपयोग सभी किसान भाई अपने-अपने खेतो में करेंगे ताकि विदिशा जिला भी उद्यानिकी नवीन विधाओं से परिपूर्ण हो सके। उक्त कार्यक्रम में जिला पंचायत कृषि समिति के सभापति श्री धनराज दांगी, सांसद प्रतिनिधि श्री कैलाश रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री जी गिरवाल के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी व विभागीय स्टाफ मौजूद रहा। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री जी गिरवाल ने बताया कि तीन दिवसीय उक्त प्रशिक्षण में जिले के तीस कृषकबंधु राजगढ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र में पहुंचकर कृषक प्रशिक्षण तथा उन्नतशील, प्रगतिशील कृषकों के यहां पहुंचकर भ्रमण करेंगे इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्र शाजापुर में पहुंचकर प्रशिक्षित होंगे वहीं सीहोर जिले की कृषि महाविद्यालय में पहुंचकर जानकारियां प्राप्त करेंगे इसके अलावा भोपाल के ईंटखेडी में स्थित फलो अनुसंधान केन्द्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान कृषकबंधु उद्यानिकी फसलो की नवीनतम जानकारियों को प्राप्त करेंगे तथा उन्नतशील व प्रगतिशील कृषकों के यहां पहुंचकर उनके द्वारा उद्यानिकी फसलों में किए गए नवाचार का स्थलीय भ्रमण कर जायजा लेंगे।

कलेक्टर सिंह ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर जिले में नवनिर्मित व पूर्व की जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्यों का जायजा लिया

विदिशा (निप्र)। भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं जल शक्ति अभियान के सेन्ट्रल नोडल आफीसर श्री शशांक मिश्रा और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप भ्रमण कर जिले में नवनिर्मित व पूर्व की जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय जायजा लिया है। भ्रमण के दौरान जल संरचनाओं के उपयोगिता दलो का गठन कर उन्हें सुरक्षा के दायित्व सौंपने के निर्देश दिए गए है वहीं जल संरचनाओं में मत्स्यपालन के कार्य कराए जाएं

उपयोगिता दलों को सुरक्षा के दायित्व सौंपने के निर्देश

ताकि स्थानीय रहवासियों को रोजगार के संसाधनो की पूर्ति हो सकें। गौरतलब हो कि जल संरचनाओं, उपयोगिता दलो में अधिक से अधिक महिला को शामिल किया गया है ताकि जल के सदुपयोग के अवधारणा को अक्षरशः प्रतिपादित किया जा सकें। संयुक्त सचिव श्री मिश्रा ने भ्रमण के दौरान संबंधितों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त जल संरचनाओं में भण्डारित जल का सिंचाई कार्यो में उपयोग ना किया जाए जिससे समीपवर्ती के जल स्त्रोत मार्च, अप्रैल माह तक में उनमें सुगमता से जल की उपलब्धता बनी रहे ताकि ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रो में निर्मित ना हो। उन्होंने उपरोक्त कार्यो से क्षेत्र में वाटर लेबल में क्या अंतर है कि जानकारियां प्राप्त की है। जल शक्ति अभियान के तहत संपादित किए जा रहे कार्यो का भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मिश्रा ने ग्यारसपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्रामो में भ्रमण कर जायजा लिया है। उन्होंने ग्राम सुआखेडी में तालाब के जीर्णद्धार कार्यो को देखा वहीं ग्राम मढीपुर में पुष्कर तालाब योजना के कार्यो का तथा ग्राम हिम्मतपुर में अमृत सरोवर के सम्पन्न हुए कार्यो का जायजा लिया इसके अलावा ग्यारसपुर के मानसरोवर तालाब का जीर्णोद्धार और अमर्रा तालाबो के कार्यो का जायजा लिया और मालादेवी मंदिर का अवलोकन किया। संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने आज ग्राम पंचायत सुआखेडी में गौशाला के समीप निर्मित तालाब के जीर्णद्धार कार्यो का अवलोकन किया और यहां यूजरग्रुप बनाए जाने तथा उपयोगकर्ता समूह को मछलीपालन के लिए तालाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। ग्राम पंचायत मढीपुर में पुष्कर धरोहर के तहत निर्मित तालाब के कैंचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने और कैंचमेंट क्षेत्र को बढाने के निर्देश दिए है ग्राम पंचायत अटारीखेजडा में भी पुष्कर धरोहर तालाब के अवलोकन दौरान स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गतिविधियो और ओडीएफ प्लस हेतु उचित क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए गए है। संयुक्त सचिव श्री मिश्रा और कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पंचायत कोलुआधामनोद के हिम्मतपुर में नवनिर्मित अमृत सरोवर तालाब का जायजा लिया और निर्माण के संबंध में किए गए कार्यो की जानकारी प्राप्त की। यहां अधिक से अधिक जल संरचनाएं रिचार्ज होने से अवगत कराया गया है स्थानीय सरपंच ने बताया कि पूर्व में गांव के जलस्त्रोत फरवरी माह तक जल प्रदाय कर पाते थे किन्तु नवीन अमृत सरोवर तालाबा बन जाने से अब अप्रैल मई तक सुगमता से जल की आपूर्ति हो रही है वहीं पशुधन को पेयजल प्राप्ति में सहूलियते हुई है। यहां मछली पालन करने तथा नवम्बर माह में इनपुट आउटपुट चैनल का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाए के निर्देश दिए गए है।

ग्राम पंचायत मढियाधामनोद के ग्राम बरीधामनोद में भी अमृत सरोवर तालाब का जायजा लिया गया है। यहां तालाब की बाउण्ड्री (बंड) पर पिचिंग का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए है। भ्रमण के दौरान ग्यारसपुर के अतिप्राचीन मानसरोवर तालाब का भी अवलोकन किया गया है। यहां जीर्णोद्धार व जन भागीदारी से सम्पन्न कराए गए जलकुंभी हटाने सहित अन्य कार्यो की जानकारियों से अवगत कराया गया है। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री पंकज जैन, जनपद सीईओ श्री राजेन्द्र जैन के अलावा आरईएस के कार्यपालन यंत्री श्री राजेन्द्र गजभिए, ग्यारसपुर तहसीलदार श्री सौरभ मालवीय, पीएमजीएसबाय के महाप्रबंधक तथा जनपद एवं आरईएस के उपयंत्री तथा एई श्री आरके दुबे मौजूद रहें।

डेंगू बीमारी के बढ़ते मरीजों के कारण कीटनाशक दवाओं का करें छिड़काव, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाएं

सुबह सवेरे सोहागपुर। नगर में डेंगू मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या को लेकर कांग्रेस जन चिंतित हो गए हैं। इसी संदर्भ को आज ब्लाक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ज़िला कलेक्टर के नाम एक

ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को संबोधित करते तहसीलदार अल्का एक्का को प्रदान किया गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि सोहागपुर ब्लाक पहले 15-20 दिनों से डेंगू मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी के कारण हड़कंप मचा हुआ है।

इससे क्षेत्र नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता बढ़ रही हैं। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सोहागपुर ब्लाक में स्थित प्राथमिक स्वस्थ केन्द्रों पर उचित स्वास्थ सुविधा नहीं हैं ।इसके कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जानता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इसके कारण शासन को तत्काल प्रभावी से आवश्यक कदम उठाएं । अन्यथा यह बीमारी महामारी का रूप में परिवर्तित हो सकती हैं ।आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि जल भराव क्षेत्रों में डेंगू मच्छर के लावा को नष्ट करने वाली दवा का अविलम्ब छिड़काव कराया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि शासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर हमारा संगठन उग्र आन्दोलन करने को बाध्य होगा। जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर सोहागपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराजसिंह पटैल, वरिष्ठ वकील मंगलसिंह रघुवंशी, गजेन्द्र सिंह चौधरी, वकील प्रांजल तिवारी,प्रकाश मालवीय,इरफ़ान ख़ान,ऋषभ दीक्षित, वकील कार्तिक शर्मा, अंकित पटैल, सरपंच राधेश्याम पटैल, प्रतीक तिवारी,नीरज चौधरी आदि उपस्थित थे।

पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने जनसुनवाई कर किया आमजन की समस्याओं का समाधान

नरसिंहपुर। पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने विधायक निवास पर जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे, जहां विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी गुहार लगाई जालम सिंह पटेल ने हर एक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

नरसिंहपुर करेली सहित आसपास के ग्रामीण जन अपनी समस्याओं की शिकायत आवेदन लेकर पहुंचे जहा उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए उनका समाधान किया कई लोग अपने गांव की सड़क आदि अन्य समस्याएं लेकर पहुंचे थे जिनका तुरंत समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया वहीं, कुछ लोग व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर आए जिनमें भूमि विवाद, पेंशन, आवास योजनाओं के लाभ आदि की मांगें शामिल थीं श्री पटेल ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा जनता के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाने वाले जालम सिंह पटेल जन सेवा का संकल्प लेकर आमजन की सेवा में समर्पित हैं जालम सिंह पटेल ने जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है और वे अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समाज और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं व्यक्ति की सेवा भावना और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जनसुनवाई में उनके संवेदनशील रवैये और त्वरित कार्यवाही ने लोगों का विश्वास और भी मजबूत किया स्थानीय निवासियों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पटेल हमेशा जनता के हित में काम करते हैं और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करते हैं उक्त जानकारी विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने दी।

पीएम जन मन योजना के कार्यों की समीक्षा

नरसिंहपुर। मप्र राज्य स्तरीय भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री दिनेश कुमार अंगारिया ने नरसिंहपुर क्षेत्रांतर्गत भारिया समुदाय से चर्चा की और पीएम जनमन योजनांतर्गत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्री अंगारिया ने निर्देश दिये कि जिले में योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार कैंप, पोस्टर आदि के माध्यम से किया जाये। बैठक में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों व लाभांवित किये गये हितग्राहियों की जानकारी से अवगत कराया गया। बैठक में वन, चिकित्सा, खाद्य, जनजातीय कार्य, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग, सीईओ जनपद करेली, ई- गर्वनेंस, आरईएस के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री दिनेश कुमार अंगारिया ने करेली विकासखंड की ग्राम पंचायत नयाखेड़ा का भ्रमण किया। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री आवास में हितग्राही को गृह प्रवेश कराया। उन्होंने वहां के निवासियों से चर्चा के साथ पीएम जनमन योजना के लाभों से सभी को अवगत कराया।

मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस

नरसिंहपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शास उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर बड़ा में रस्साकसी, दौड़,कबड्डी के खेल आयोजित हुए। आयोजक खेल विभाग के युवा समन्वयक, कबड्डी प्रशिक्षक विकास शर्मा द्वारा खिलाड़ियों एवं छात्रों को जीवन शैली में खेलों के महत्व को बताया,,खेलों में रुचि रखने वाले पूर्व खिलाड़ी शिक्षक राजेश शर्मा के द्वारा हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जीवनी के बारे में बताया गया। आयोजन में पूर्व खिलाड़ी विमलेश दुबे, भूपेंद्र अमित शर्मा, प्रतीक शर्मा एवं शाला परिवार के शिक्षक,शिक्षिकाओं द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। अंत में खिलाड़ीयों को खेल विभाग की जिला खेल युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव द्वारा उपलब्ध कराई गई खेल किट का वितरण किया गया।। कार्यक्रम का आभार प्रभारी प्राचार्य ब्रजेश शर्मा द्वारा किया गया।

तोड़े गए बजरिया स्कूल के कागजात देने से कतरा रही नगरपालिका..

मानो किसी गुप्त ऐजेंडे पर काम कर रही हो नगरपालिका....

नर्मदापुरम। पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा बनाए गए शाला भवन को जर्जर कहकर नगरपालिका ने उसे समय पूर्व तोड़ तो दिया लेकिन उसी बजरिया स्कूल भवनों को तोड़कर अब नगरपालिका जानकारी देने से कतरा रही। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई बजरिया स्कूल को तोड़े जाने की शुरुआती दौर के नोटशीट से लेकर आज दिनांक तक स्कूल भवन तोड़ने तक जितनी भी कार्रवाई नगरपालिका ने परिषद हो या पीआईसी से प्रस्तावित अनुमति, अनुशंसा के लिए शिक्षा विभाग सहित लोकनिर्माण विभाग की रिपोर्ट और ऑडिटोरियम निर्माण के लिए की गई कसरत के पत्रों की सत्य प्रतिलिपि मांगे जाने पर उसने एक महीने की समयावधि निकाल दी लेकिन बजरिया स्कूल से संबंधित कागजात नहीं दे पाई। आवेदनकर्ता की प्रथम अपील ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन को प्रस्तुत की गई। वहां भी समयावधि में एक पत्र नगरपालिका को लिखने के सिवा दूसरा पत्र नहीं बढ़ पाया, समयावधि पूर्ण होने के बाद अब जब ज्वाईंट डायरेक्टर सुरेश बेलिया को द्वितीय अपील में जाने के लिए आवेदन पत्र पर फैसला देने के लिए कारवाई हेतु कहा। तब उन्होंने संबंधित को नगरपालिका के संबंधित सब- इंजिनियर महेंद्र तोमर से मिलने को कहा यहां सब- इंजिनियर महेंद्र तोमर उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर के कहने पर भी जानकारी नहीं दे पा रहे। लगभग ढाई महीने से सूचना का अधिकार के तहत नहीं मिल पा रही जानकारी के पीछे आखिर क्या राज हो सकता जिसे इस काम के प्रभारी अधिकारी महेंद्र तोमर देने से कतरा रहे। यह अबूझ पहेली बन गया। गौरतलब हो नगरपालिका की जमीन 15/1 पर रसूख के दम पर अवैध भवन निर्माण कर स्कूल चलाया जा रहा इतना ही नहीं सड़क किनारे नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर काम्प्लेक्स बना कर उससे लाखों रुपए किराया वसूला जा रहा। पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी और विधायक की दखलंदाजी ने नगर की धरोहर प्राथमिक शाला बजरिया को अपने मनसूबे नुसार तुड़वाकर सरकारी पैसों से निर्मित होने वाले आडिटोरियम को शायद निजी कब्जे में लिए जाने का एजेंडा अतिक्रमण कर्ता ने बनाऐ हो..? अरबों की भूमि हथियाने को लेकर गुप्त ऐजेंडे पर काम हो रहा जिसमें कलेक्टर की भूमिका भी अहम मानी जाती है।

दो कविताएँ

राजकुमार कुम्भज

1. कष्टराग-एक

यहाँ हैं, तो क्या वहाँ नहीं हैं?
कौन कहता है कि कष्ट कहाँ-कहाँ नहीं हैं?
जो यहाँ हैं, वो वहाँ-वहाँ भी हैं
और जो वहाँ हैं, वो यहाँ-यहाँ भी हैं
कष्ट हैं कि नष्ट नहीं हैं, हर कहीं हैं
फिर एक कष्ट हो, एक जगह हो, तटस्थ हो
तो बताएँ भी कि कष्ट कहाँ नहीं हैं?
ऊपर से चादर है परत-दर-परत बर्फ़ की,
भीतर ही भीतर धड़क रही हैं ज्वालाएँ
ऊपर से कलियाँ हैं गुलाब की-सी शबाब पर
भीतर ही भीतर हलाहल, काँटों भरी मालाएँ
दीप जलाओ, दीप जलाओ, बड़ा अँधेरा है
ग़ैर तो हार गए, अपनों ने घेरा है
लहर-लहर तड़प है, जप-तप करती हड़प है
कौन कहता है कि झड़प कहाँ-कहाँ नहीं हैं?
यहाँ हैं, तो क्या वहाँ नहीं हैं?

2. कष्टराग-दो

कारण नहीं, तो कष्ट नहीं
किसी न किसी कारण ही कोई कष्ट होता है
कष्ट होता है, कारण होता है, आदमी होता है
आदमी वही आदमी होता है जिसको कष्ट होता है
कष्ट नहीं, आदमी नहीं, कारण नहीं
बग़ैर कारण, बग़ैर कष्ट, आदमी नहीं
दूर-दूर कष्ट नहीं, दूर-दूर आदमी नहीं
आदमी से दूर-दूर कष्ट नहीं
कष्ट से दूर-दूर आदमी नहीं
आदमी भी आदमी नहीं, अगर कष्ट नहीं
कारण नहीं, तो कष्ट नहीं.

अतिथि शिक्षकों की सांध्य- रात्रि कालीन ब्लाक स्तर बैठक सम्पन्न

2 व 5 सितंबर की रैलियों की हो रही तैयारियां

नरसिंहपुर। अतिथि शिक्षकों के महासंघ के प्रान्त कार्यकर्ता व जिला अध्यक्ष एस के सोनी ने कदेली नर. में सांध्य-रात्री कालीन बैठक आयोजित करते हुए बताया कि महासंघ के आवाहन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आयोजित अति.शि. महापंचायत के आयोजन को दिनांक 2 सितंबर 2024 एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2024 के अवसर पर क्रमशः प्रत्येक जिला मुख्यालय में और राजधानी भोपाल स्तर पर आक्रोशित अति. शि. हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ में घोषणाओं को पूरा करें का आवेदन पत्र लेकर सड़कों पर उतरेंगे और महापंचायत के किए गए वादों के आदेश जारी करने के लिए निवेदन करेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए अतिथि शिक्षकों में अद्भुत उत्साह व्याप्त है मप्र सरकार अति.शि. की महापंचायत होने पर भी भविष्य को सुरक्षित नहीं कर रही है जिसका परिणाम वर्तमान में उनको स्कूलों से बाहर किए जाने के रूप में स्पष्ट दिख रहा है। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में दिनांक 02 सितंबर 2024 को ज्ञापन, आवेदन एवं तिरंगा रैली एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को महासंघ का ज्ञापन व व्यक्तिगत आवेदन के अवसर एवं 5 सितंबर 24 भोपाल की विशाल तिरंगा रैली के लिए नरसिंहपुर ब्लॉक व नगर की एक सांध्य- रात्री कालीन आवश्यक बैठक का आयोजन धनारे कलोनी में बृजेंद्र नेमा केनिवास पर किया गया।इस बैठक में सभी वक्ताओं ने अति. शि. के असुरक्षित भविष्य एवं सरकार के द्वारा महापंचायत के बातों का पूरा न करने के लिए अपना आक्रोश और चिंतन प्रकट किया। उक्त दोनों कार्यक्रमों के लिए आवश्यक रणनीति का निर्माण किया गया। महा पंचायत की घोषणयो के लिए सभी संगठन एक है और इसमें ही सभी अतिथि शिक्षकों का हित छुपा हुआ है चर्चा की गई । नए ज्वाइन अति. शि. भी इन कार्यक्रमों में सहभागिता देंगे आवाहन किया गया। जागरूक अतिथि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सूची बना कर कम से कम 10 अन्य को प्रेरित करें।महिला अति. शि. जागरण के लिए 09 सदस्यीय नव शक्ति महिला प्रेरणा मंडल का ब्लाक स्तरीय गठन किया गया जिसमें प्रतिभा सिंह ,जया सोनी, सरिता

गुप्ता ,नजमा खान आदि को रखा गया है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष बृजेंद्र नेमा, ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा, शशिकांत मिश्र, अरुण पाठक,सरिता गुप्ता,रीना पाठक,नेहा पालीवाल,जया सोनी, शिवम नेमा,नाजिया खान,प्रतिभा जाट,भूपाल पटेल,चंद्रभान पटेल, मनीष कुमार उदेनिया,सीताराम पटेलप्रदीप कुमार, राजकुमार चौधरी, अंकित जाट, सुनील विश्वकर्मा, मनीष त्रिपाठी,शिवम साहू,पी.एल.खरे, भूपेन्द कुमार शर्मा, पंकज राजपूत व भगवत जाट, परबेज खान अतिथि शिक्षक परिजन के अलावा अन्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

देवास में रैन वाटर हार्वेस्टिंग विषय पर कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

देवास। बेटी बचाओ-बेटी पढाओं एवं विभागीय आंगनवाड़ी भवनों को सक्षम आगनवाड़ी में उन्नत करने के लिएपोषण वाटिका एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग विषय पर कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत देवास के सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेलम बघेल, मास्टर ट्रेनर श्री रवि जायसवाल एवं श्रीमती लिपि भार्गव, कृषि विज्ञानिक श्रीमती अरविंदु, श्री मोहन वर्मा, सुश्री यशिका रघुवंशी उपस्थित रही।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गए एवं समय पर उक्त घटकों का निमार्ण कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया।

सहायक संचालक श्री संजय भारद्वाज के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बेटी

बचाओ बेटी पढाओ योजना महिला सशक्ति करण के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है।

मास्टर ट्रेनर श्री रवि जायसवाल एवं श्रीमती लिपि भार्गव द्वारा पोषण वाटिका एवं मोहन वर्मा द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई,कि रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे लिये किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। हम सभी को अपने घर पर पोषण वाटिका एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण करना चाहिए

कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण

जिला चिकित्सालय परिसर के शासकीय आवास में कोई भी चिकित्सक प्रायवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे : कलेक्टर श्री गुप्ता

देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय ने शुक्रवार को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम श्री प्रवीण फुलपगारे, एएसपी श्री जयवीर सिंह भदौरिया, नगर निगम आयुक्त श्री रजनीश कसेरा, एसडीएम श्री बिहारीसिंह, सीएसपी श्री दिशेष अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक शर्मा, सीएमएचओ डॉ. सरोजनी जेम्स बेक, सिविल सर्जन डॉ. एस.के.खरे, आर.एम.ओ. डॉ. अजय पटेल, अमलतास अस्पताल, आदियोगी अस्पताल, विनायक अस्पताल के संचालक सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, चिकित्सक एवं सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।।

कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर में बने कार्यालय एनआरसी, जन्म-मृत्यु शाखा, पीएम रूम सहित मैटरनिटी भवन के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीएम रूम का विस्तार कर एक और रूम बनाया जाए तथा वहां पर अन्य सुविधाएं कराई जाएं। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि सीएमएचओ कार्यालय, जिला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, मैटरनिटी विंग के सभी रास्तों पर लाइट की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने बंद पड़ी लाइट को शीघ्र चालु करने के निर्देश नगर निगम को दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के पीछे स्ट्रीट लाइट लगाए। नर्सिंग कॉलेज और परिसर में साफ-सफाई की जाए। अस्पताल के परिसर में हाई क्वालिटी के कैमरे लगाई जाए तथा एक कंट्रोल रूम स्थापित कर सिस्टम लगाया जाए। कंट्रोल रूम के माध्यम से अस्पताल में निरन्तर निगरानी रखी जाए। अस्पताल या परिसर में किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर तुरंत अनाउंसमेंट किया जाए। अस्पताल परिसर में स्टॉफ पॉर्किंग, मैटरनिटी भवन के पास करवाये वहां दीवार पर मार्किंग करें तथा अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस के लिए रिर्जव स्थान रखा जावे। नवीन

भवन में 4 पुलिस जवान की ड्यूटी रहेगी। इनके द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जावेगी। जिला अस्पताल के लिए चिकित्सक और स्टॉफ के क्वार्टर बनाए गए हैं वहां की बाउंड्रीवालों को तार फैंसिंग से कवर किया जाए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधन के लिए सेक्युरिटी गार्ड की व्यवस्था की जाए। अस्पताल परिसर में कार्य करने वाले जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, पार्किंग व्यवस्था, सफाई कर्मचारी, लॉन्ड्री, खाना बनाने वाले या अन्य आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों का पुलिस वैरीफिकेशन होने के पश्चात ही कार्य पर रखा जाएं। अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ सहित अन्य स्टॉफ और आउट सोर्स एजेंसी के कर्मचारियों सभी का आईडी कार्ड अनिवार्य किया जाए तथा ये सभी निर्धारित ड्रेस कोड में ही कार्य करेंगे। अस्पताल परिसर में अनुपयोगी कबाड़ है, उसे तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए अस्पताल के स्टॉफ के वाहनों पर बड़ा स्टीकर लगाए, जिससे उनके वाहनों की पहचान हो सकें।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में संचालित 100 बेड से अधिक के अस्पतालों में जिला अस्पताल, अमलतास अस्पताल, आदियोगी और विनायक अस्पताल के संचालनकर्ता और सिविल सर्जन जिला अस्पताल को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल में मरीज के साथ एक ही अटेंडर रहेगा। इसके लिए भर्ती के समय 2 पास बनाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाए, सेक्युरिटी गार्ड द्वारा नियम का पालन करवायें। एक मरीज के साथ एक अटेंडर ही रहे इसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रबंधक द्वारा की जाए। सिक्यूरिटी से संबंधित प्रति सप्ताह या 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पुलिस को भेजेंगे। अस्पताल में नियमित आकस्मिक मॉनिटरिंग एसडीएम और तहसीलदार द्वारा की जाएगी।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान देखा कि चिकित्सकों को परिसर में सरकारी आवास आवंटित किए गए पर प्रायवेट प्रेक्टिस के बोर्ड लगे है सिविल सर्जन डॉ खरे को निर्देश दिये कि परिसर के शासकीय आवास में कोई भी चिकित्सक प्रायवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे। इसके लिए लिखित में निर्देश जारी करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि नवीन अस्पताल एवं पुराने अस्पताल के मरीजों को दवाई का वितरण एक ही जगह से किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने एनआरसी कक्ष का निरीक्षण तथा 16 बेड एनआरसी में 3 बच्चे भर्ती होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक शर्मा को निर्देश दिये कि देवास शहरी क्षेत्र के महिला बाल विकास विभाग के 2 सुपरवाईजर का वेतन रोकने के निर्देश दिये। भर्ती बच्चों कि माताओं से चर्चा की और चिकित्सक स्टॉफ को निर्देश दिये कि सभी को जागरूक कर अधिक से अधिक बच्चों को भर्ती करें। जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र शाखा का निरीक्षण किया। अधिकतर बच्चों के समय पर प्रमाण-पत्र नहीं मिलने कि शिकायत पर स्टॉफ से जानकारी ली तथा सख्त निर्देश दिये कि पुराने बेकलॉक को शीघ्र खत्म करें और वर्तमान में डिस्चार्ज होने के बाद नियमित बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिये जाने के निर्देश सिविल सर्जन डॉ एस के खरे को दिये।

11 महीने बाद भी बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क में एक ईंट नहीं जुड़ी!

भूमिपूजन में 2.18 करोड़ का लगा था 'टेंट', 48 लाख का भोजन

भोपाल। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में करीब 11 महीने पहले बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क की नींव रखी गई थी। इस पार्क का निर्माण जावद विधानसभा क्षेत्र में होनी है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बॉयोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण 40 हेक्टेयर में होना था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने फंड भी अलॉट कर दिया है लेकिन साइट पर एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई है। जबकि इसके भूमिपूजन में लगभग पौने तीन करोड़ रुपए की राशि खर्च की गयी थी। 26 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया था। वर्तमान विधायक ओमप्रकाश सखलेचा उस समय एमएसएमई मंत्री थे, तब उन्होंने इस पार्क को लेकर कई तरह की बातें की थी, लेकिन विडंबना है कि भूमि पूजन व घोषणाओं के एक साल बाद भी मध्यप्रदेश का पहला बायो टेक्नॉलॉजी पार्क मूर्तरूप नहीं ले पाया। नीमच जिले की सरवानिया महाराज नगर परिषद के पास गांव आमलीभाट के पास करीब 40 हेक्टेयर जमीन पर इस बायो पार्क का निर्माण होना था। एक साल बीतने के बाद भी यहां एक भी ईंट नहीं लग पाई। जहां पार्क बनना है, वहां वर्तमान में कीचड़ फैला है। बजट में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद प्रदेश का पहला बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क का कार्य शुरू तक नहीं हो पाया। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि जब भूमिपूजन इसका हुआ

था, तब सरकार की तरफ से मंजूर फंड से ज्यादा की राशि खर्च की गई। वहीं, मेपकास्ट के जरिए इसका आयोजन किया गया था। भूमिपूजन और विज्ञान महोत्सव के लिए इवेंट मैनेजमेंट करनी वाली कंपनी को 2 करोड़ 18 लाख 38 हजार 282 रुपए का भुगतान किया गया। इसमें कंपनी की तरफ से टेंट, डोम, लाइट, साउंड सिस्टम, कूलर, कुर्सी, फैन, एसी, लाइव स्ट्रीमिंग, कट आउट, फूल और वीडियो ग्राफी समेत अन्य खर्च थे। साथ ही भोजन की व्यवस्था को लेकर 47 लाख 80 हजार 440 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क का काम कब शुरू होगा और खर्च को लेकर जब मेपकास्ट के निदेश डॉ अनिल कोठारी से मीडिया ने बात की। उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति के बाद ही खर्च किए गए हैं। डॉ अनिल कोठारी ने सभी आरोपों को नकार दिया। साथ ही कहा कि प्रशासकीय अनुमति के बाद ही सारे कार्य किए गए हैं। वहीं, काम कब से शुरू होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग कंपनी बन रही है। सेक्शन आठ के अंतर्गत कंपनी गठन की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी बनने के बाद फंड रिलीज हो जाएगा। कंपनी बनने के बाद काम शुरू हो जाएगा। तत्कालीन मंत्री और स्थानीय विधायक ओमप्रकाश सखलेचा ने नवभारत टाइम्स.कॉम से कहा कि फंड अलॉट हो गया। एक पॉलिसी अटकी है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। केंद्र सरकार से इसके लिए फंड आ गया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तैयार हो गई हैं। हालांकि भूमि पूजन में खर्च को लेकर तत्कालीन मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाने का मुख्य उद्देश्य नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके लिए यहां 8 उच्च-स्तरीय प्रायोगशाला स्थापित होनी है। इनमें फाइटो फॉर्मास्यूटिकल, ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला, हर्बल फॉर्म्यूलेशन, पादप ऊतक संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन, माइक्रोबियल बायो-टेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, जैव सूचना और फोर्टिफाइड फूड प्रयोगशाला शामिल हैं। नीमच जिले की जावद तहसील के छोटे से गांव आमलीभाट और बरखेड़ा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क शुरू नहीं होने से जिला कई अवसरों से वंचित रह गया, क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट देश के लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर, बेंगलुरु और सिर्फ गुवाहाटी में हैं। एक प्रोजेक्ट केरल के शहर कोच्चि में हैं, जो राज्य की वाणिज्यिक राजधानी है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर में है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह पहला प्रोजेक्ट नीमच जिले में प्रस्तावित है। ओमप्रकाश सखलेचा के एमएसएमई मंत्री बनने से पहले यह प्रोजेक्ट भोपाल में लगना था, लेकिन बाद में इसके स्थान में परिवर्तन किया गया। पूर्व में केंद्र की पहल पर 2020 में भोपाल के लिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर प्रस्तावित हुआ था, लेकिन तत्कालीन मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने अपने क्षेत्र में 79 औषधीय उत्पादन व रकबा अधिक होने का हवाला देकर इस प्रोजेक्ट को भोपाल से जावद लाने के प्रयास किए।

ताज संरक्षण की पाबंदियों से परेशान इंडस्ट्री ग्वालियर होंगी शिफ्ट

आगरा का चमड़ा उद्योग, फिरोजाबाद से कांच और चूड़ी बनाने वाले बड़े इंडस्ट्रीज भी आने को तैयार

भोपाल। आगरा सहित यूपी के चार जिलों के फुटवियर, चमड़ा, कांच, ऑटो पार्ट्स सहित कई अन्य सैग्मेंट कारोबारी ग्वालियर-चंबल अंचल में आने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आगरा में ताज महल की सुरक्षा व संरक्षण के लिए बनाए गए ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) में ताजमहल से 120 किमी के एरिया को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी जद में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व एटा के बड़े इंडस्ट्रीज एरिया शामिल हो गए हैं। जहां कई उद्योग स्थापित हैं। फिरोजाबाद में तो कांच और चूड़ी बनाने के बड़े उद्योग हैं। अब वहां के कारोबारी ग्वालियर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। टीटीजेड के कारण इन चारों जिलों में न तो पुराने उद्योगों का पर्याप्त विस्तार हो पा रहा है और न नए निवेश बड़े उद्योग के रूप में आ पा रहे हैं। यहां के उद्योगपति नई जगह की तलाश में थे, इनकी तलाश उस समय पूरी होती नजर आई जब आगरा के उद्योगपतियों ने बुधवार को ग्वालियर में हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन लोगों की बात सुनने के बाद एमपीआईडीसी के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे उप्र और मप्र के उद्योग विभाग में उद्योगपतियों की बात करें। साथ ही रिपोर्ट देकर बताएं कि एमपीआईडीसी ने क्या क्या कार्रवाई की। जिससे उद्योगों का विस्तार रुका सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में सुनवाई करते हुए 1992 में फैसला दिया था। जिसके अनुसार ताजमहल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) बनाया गया। ये जोन 120 किलोमीटर में बनाया, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और एटा के इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा जिन उद्योगों से प्रदूषण फैलता है। उन्हें बंद किया जाए या फिर वे स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों पर जाएं। जिसके बाद चिमनी आधारित कई उद्योग बंद हो

गए। वहीं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटी जोन में उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए एडहॉक मॉनिटरियम लागू कर दिया। इस व्यवस्था के अनुसार उद्योगों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) की एनओसी अनिवार्य कर दी गई। इन सभी नई पाबंदी एवं व्यवस्थाओं के कारण बड़े उद्योगों का विस्तार एवं स्थापना दोनों ही अटक गए हैं।

ग्वालियर में सब्सिडी और रोड कनेक्टिविटी का फायदा

मप्र सरकार निवेशकों को उद्योगों पर श्रेणीवार सब्सिडी दे रही है। बीते दिनों प्रदेश के उद्योगपतियों के खाते में डीबीटी से सब्सिडी भेजी गई है। ग्वालियर से आगरा के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम जल्द शुरू होगा। इससे आगरा-ग्वालियर की दूरी 88 किमी रह जाएगी। पुराने 4 लेन हाइवे के साथ एक्सप्रेस वे से रोड कनेक्टिविटी का लाभ उद्योगों को मिलेगा। 6उद्योग इकाईयों को लेकर कोई सख्त गाइडलाइन नहीं है। जिससे किसी चुनौती का सामना करना पड़े। इंडस्ट्रियल एरिया घनी आबादी में नहीं हैं।

वाटर कैनन के प्रेशर से बैरिकेड से गिरे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी

भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन,कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस में ले गई पुलिस

भोपाल। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का घेराव करने आगे बढ़े। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया। पानी के प्रेशर से जीतू पटवारी बैरिकेड से गिर गए। कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस भी छोड़ी। इसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों से ले गई। इससे पहले मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये सरकार मोहन यादव और बीजेपी की सरकार नहीं माफियाओं की सरकार है। आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव आदि शामिल हुए। मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया, यूथ कांग्रेस ने दो महीने पहले 'क्या हुआ तेरा वादा' अभियान शुरू किया था। इसमें करीब साढ़े चार लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई हैं। आज ये पोस्ट कार्ड सीएम डॉ. मोहन यादव को सौंपने जा रहे थे। बता दें, पिछले आठ दिन में कांग्रेस का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है।

पटवारी बोले- खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी जाएगी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता अपने खून की आखिरी बूंद तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ेगा। किसानों की एमएसपी, धान और सोयाबीन के दाम और ढाई लाख नौकरियां जब तक सरकार नहीं देगी, खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहनों और दलितों पर अत्याचार इस सरकार में हो रहा है। ये माफिया की सरकार है। गुजरात से प्रदर्शन में शामिल होने आई प्रियंका पटेल ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। आंसू गैस के गोले छोड़े। कई साथियों को चोट लग गई। युवाओं को साथ हो रही बर्बरता गलत है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा। हम युवाओं के मुद्दे उनके हक की बात रख रहे थे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि हम युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी मांग रहे हैं। पिछले पांच साल में 20 एग्जाम हुए। 30 हजार लोगों को अपाइंटमेंट दिया। अब तक एक भी जॉइन नहीं हुआ। सरकार हम पर लाठी चला रही हैं। भोपाल में प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर बसों में ले गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। पानी के प्रेशर से पटवारी नीचे गिर गए। हरदा से कांग्रेस विधायक आरके दोगने ने कहा कि हमारी सभा हुई। इसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से सीएम हाउस की ओर जा रहे थे। बेरिकेड से पहले ही रोक लिया गया। वाटर कैनन चलाया गया। आंसू गैस छोड़ी गई। धक्का-मुक्की कर कार्यकर्ताओं को भगाया गया। ये दुर्भाग्य है। हम जनता की मांग लेकर जा रहे थे। सरकार को सुनना चाहिए। जनता की जायज मांगें हैं। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। युवा परेशान है। हम सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बात रखना चाहते थे। भगदड़ में कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। सरकार को लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए।

इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम में झमाझम बारिश

31 अगस्त से जबलपुर-रीवा में तेज बारिश; प्रदेश में अब तक 33.6 इंच बारिश

भोपाल। मध्यप्रदेश में 31 अगस्त से मौसम का नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। यह 2 दिन राज्य के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में तेज बारिश कराएगा। शुक्रवार शाम को भोपाल और नर्मदापुरम में तेज बारिश हुई। वहीं इंदौर में दोपहर 1 बजे से तेज पानी गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज मालवा-निमाड़ यानी इंदौर-उज्जैन संभाग में कहीं-कहीं तीखी धूप रहेगी। जबलपुर, ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक प्रकाश दावले ने बताया, एक मानसून ट्रफ प्रदेश के शिवपुरी, सीधी से होकर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया में मर्ज हो रहा है। एक-दो दिन बाद यह असर दिखाते हुए आगे

बढ़ेगा। इसकी वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मध्यप्रदेश में अब तक 33.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 90 प्रतिशत है। 3.7 इंच पानी और गिरते ही प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। मंडला और सिवनी ऐसे जिले हैं, जहां 45-46 इंच पानी गिर चुका है, जबकि रीवा में सबसे कम 22.3 इंच बारिश ही हुई है। अब सितंबर में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर की शुरुआत भी तेज बारिश के साथ होगी। प्रदेश के बड़े डैम 90 प्रतिशत से ज्यादा भर चुके हैं। भोपाल के तीनों डैम- कलियासोत, केरवा और भदभदा के गेट खुल चुके हैं, जबकि भोपाल के पास कोलार डैम के 8 में से 4 गेट खोले जा चुके हैं। इस साल पूरे जबलपुर संभाग में तेज बारिश हो रही है। मंडला जिला सबसे आगे हैं। यहां 46 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। सिवनी में 45 इंच बारिश हो गई है। सबसे ज्यादा बारिश के मामले में प्रदेश के टॉप-10 जिलों में सीधी, श्योपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर जिले भी शामिल हैं।

राजधानी में युवा संसद प्रभारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशिक्षण

केसी गुप्ता बोले-संसदीय व्यवस्था की मजबूती के लिए युवा संसद प्रभारियों की भूमिका महत्वपूर्ण

भोपाल। भोपाल के पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में आज युवा संसद प्रभारियों का प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग श्री केसी गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव ने युवा संसद प्रभारियों को बताया कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में अपनी विशिष्टता के कारण विशेष पहचान रखता है। देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि युवा संसद प्रभारियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपने शैक्षणिक संस्थानों में युवा संसद का मंचन कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों

की सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा देश के भविष्य हैं। इन्हें संसदीय प्रणाली का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम को डॉ. एन.के. थापक कुलगुरू एलएनसीटी विश्वविद्यालय एवं डॉ. धर्मेन्द्र पारे निदेशक जनजातीय संग्रहालय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संसदीय पीठ की संचालक डॉ. प्रतिमा यादव ने बताया कि यह संसदीय पीठ वर्ष 1998 से निरंतर संचालित हो रही है। संसदीय पीठ के माध्यम से बच्चों और युवाओं को संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देने के प्रयास किये जा रहे हैं। संसदीय पीठ में हुए आज के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के स्कूलों और बरकतउल्ला विश्विविद्यालय भोपाल के कॉलेजों के युवा संसद प्रभारियों को युवा संसद मंचन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के उप सचिव श्री ए.बी. आचार्य ने युवा संसद प्रभारियों के सवालों के जवाब दिये। उन्होंने कहा कि नागरिकों के अनुशासन और निष्ठा से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

प्रदेश में 275 सीएम राइज स्कूल हो रहे संचालित

बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए दी जा रही है निःशुल्क परिवहन सेवा

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल संचालित हो रहे हैं। दूसरे चरण में प्रदेश में 5 हजार 986 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश के सीएम राइज स्कूल योजना का पहला सर्व-सुविधायुक्त भवन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाना जिला शाजापुर में लोकार्पित हो चुका है। पहले चरण में 270 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 247 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 122 सीएम राइज स्कूल भवन

निर्माण पूरे कर लिये जायेंगे। सीएम राइज स्कूल योजना को गुणवत्तायुक्त समावेशी शिक्षा एवं सुशासन की श्रेणी में वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिये निःशुल्क परिवहन सेवा भी प्रारंभ की गई है।

32 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती

प्रदेश में पिछले तीन शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 32 हजार 82 शिक्षकों की भर्ती की गई है। प्रदेश में बच्चे स्कूल सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें, इसके लिये वर्ष 2024-25 में 4 लाख 50 हजार पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जायेंगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिये ग्रामीण शिक्षकों को आवास योजना की स्वीकृति दी गई है। कक्षा एक और दो के बच्चों के लिये राज्य सरकार ने दक्षता फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इसमें निधार्रित लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित की अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं लर्निंग किट तैयार कर वितरित किये गये हैं। प्रदेश में सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 में अध्ययनरत 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में 57 करोड़ रूपये की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई है।

केंद्र से केन बेतवा लिंक परियोजना का रकबा बढ़ाने को मंजूरी

- अन्य योजनाओं पर 1150 करोड़ मिलेगे, दिल्ली से एमपी को सौगातें
- सीएम मोहन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट मुलाकात की। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात सीआर पाटिल के कार्यालय सीजीओ कांप्लेक्स हुई। सीएम मोहन ने केंद्रीय मंत्री पाटिल से इस दौरान नदी जोड़ो परियोजना और केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। मध्यप्रदेश नदी-जोड़ो अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी और यूपी महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे अलग परियोजना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी। बुंदेलखंड पानी के अभाव में यह क्षेत्र संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है।

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। सीएम मोहन ने आग्रह किया कि राज्य को दौधन बांध एवं लिंक नहर के भू-अर्जन एवं पुनर्विस्थापन हेतु 1150 करोड़ रुपए राशि केन्द्र से प्राप्त होना शेष है। जिसे केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र जारी करवाने का आश्वासन दिया।